



ग्राम पंचायत विकास योजना
'सबकी योजना सबका विकास'
2 अक्टूबर - 31 दिसंबर 2018

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण
प्रशिक्षण नियमावली

सितंबर 2018



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 30

विषय-सूची

सत्र 1: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अभिविन्यास

- 1.1 नियमावली की संरचना और विषय-सूची
- 1.2 प्रशिक्षण सुविधाप्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश
- 1.3 प्रतिभागियों के लिए दिशानिर्देश

सत्र 2: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण की प्रस्तावना

- 2.1 पीआरआई के संवैधानिक अधिदेश
- 2.2 गरीबों के संस्थान
- 2.3 स्व सहायता समूह और लोकतांत्रिक स्थान
- 2.4 पीआरआई-सीबीओ अनुबंध
- 2.5 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

सत्र 3: विकास में ग्राम सीबीओ और उनकी भूमिका

- 3.1 समुदाय आधारित संगठन
- 3.2 स्व-सहायता
- 3.3 उपयोगकर्ता समूह
- 3.4 युवा क्लब
- 3.5 महिला मंडल
- 3.6 लाभार्थी समितियां
- 3.7 संयुक्त वन प्रबंधन समूह
- 3.8 ग्राम विकास में सीबीओ की भूमिका

सत्र 4: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण

- 4.1 अभिसरण के लिए आवश्यकता और अवसर
- 4.2 पीआरआई-आरएचजी अभिसरण के उद्देश्य
- 4.3 अभिसरण का औचित्य
- 4.4 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के क्षेत्र

सत्र 5: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में भिन्नताओं की भूमिका

- 5.1 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में ग्राम पंचायत की भूमिका
- 5.2 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में एसएचजी की भूमिका
- 5.3 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में राज्य सरकार की भूमिका
- 5.4 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में एसआरएलएम की भूमिका

सत्र 6: गरीबी को कम करने के लिए अभिसरण को सक्षम करना

- 6.1 सहभागी मूल्यांकन और योजना
- 6.2 हकदारी का सहभागी मूल्यांकन (पीईई):
- 6.3 हकदारी अभिगम योजना (ईएपी)
- 6.4 जीपी स्तर पर गरीबी न्यूनीकरण योजना
- 6.5 जीपीडीपी के साथ एकीकरण

सत्र 7: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना-

- 7.1 राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ)
- 7.2 परियोजना लक्ष्य
- 7.3 एनआरओ के सिद्धांतों का मार्गदर्शन
- 7.4 सीबीओ-पीआरआई अभिसरण परियोजना राज्य
- 7.5 परियोजना का परिणाम तंत्र

सत्र 8: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण का अपेक्षित निर्गम और परिणाम

- 8.1 अपेक्षित निर्गम
- 8.2 अपेक्षित परिणाम

अनुलग्नक 1: प्रमुख आरडी कार्यक्रमों में पीआरआई और सीबीओ की भूमिका और जिम्मेदारी

अनुलग्नक 2: असम में पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना का मामला अध्ययन

अनुलग्नक 3: ओडिशा में पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना का मामला अध्ययन

अनुलग्नक 4: जीपी गरीबी न्यूनीकरण योजना का मॉडल प्रारूप

प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचना

सत्र विषय /	सत्र उद्देश्य	निवेश	अपेक्षित परिणाम
दिन- 1			
सत्र 1: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अभिविन्यास	प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण पद्धति की प्रतिभागियों को जानकारी देना प्रत्येक प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से प्रमुख मुद्दों की स्थापना करना	प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना के बारे में समझाना प्रशिक्षण सुविधा और प्रतिभागियों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों पर एक जानकारी प्रदान करना	प्रतिभागी पीआरआई-अभिसरण सीबीओ पर कार्यक्रम प्रशिक्षण होंगे उन्मुख
सत्र 2: पीआरआई सीबीओ-अभिसरणकी प्रस्तावना	आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए पीआरआई के संवैधानिक जनादेश सीबीओ के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की रणनीति सीबीओ और ग्राम पंचायतों के बीच परिचालन संबंध को स्पष्ट करना पीआरआई सीबीओ-लिए के अभिसरणडीएवाई एनआरएलएम संरचना की प्रस्तावना	पीआरआई के संवैधानिक अधिदेश का विवरण देना गरीबों के संस्थान , एसएचजी की अवधारणा स्पष्ट करना स्थानीय विकास में पीआरआई और सीबीओ की भूमिका का विवरण देना प्रशासन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से उन्हें शामिल करने के लिए गरीबों के संगठनों को कैसे मजबूत किया जाता है	प्रतिभागियों को ग्राम स्तर पर गरीबों के संस्थानों का विवरण मिलता है जो गरीबों को स्थान, विचार और संसाधन प्रदान करते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से बेहतर परिणाम पाने के लिए साथ कार्य करने का पीआरआई सीबीओ-को महत्व के संयोजन समझना
सत्र 3: सीबीओ और ग्राम विकास में उनकी भूमिका	सीबीओ का अर्थ और अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीओ के संचालन के विभिन्न प्रकार ग्रामीण विकास में सीबीओ	गांव के विकास में सीबीओ एसएचजी / भूमिका की संघों	प्रतिभागियों को सीबीओ और उनके संघ पर स्पष्टता मिलेगी जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत विकसित हुई

	भूमिका निभा सकते हैं		
सत्र 4: पीआरआई -सीबीओ अभिसरण	अभिसरण के लिए आवश्यकता और अवसर पीआरआई सीबीओ-उद्देश्य के अभिसरण अभिसरण के औचित्य और सिद्धांत ऐसे क्षेत्र जहां पीआरआई-काम से ढंग प्रभावी सीबीओ हैं सकते कर	सीबीओ गांव के विकास के लिए पीआरआई के साथ निर्बाध रूप से काम करता है गरीबों के अधिकारों के लिए गरीबों की पहुंच को मजबूत करने और बेहतर सेवा वितरण के लिए स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एसएचजी नेटवर्क कैसे काम करता है	प्रतिभागियों को सेवा वितरण एजेंसियों के रूप में उभर रहे सीबीओ के बारे में जानकारी मिलती है • स्थानीय समुदायों द्वारा कैसे अभिनव कार्य किए जा सकते हैं समुदाय आधारित संस्थानों को शामिल करके सहभागी योजना की उपयोगिता के बारे में बढ़ती समझ
दिन 2-			
सत्र 5: पीआरआई सीबीओ-विभिन्न में अभिसरण भूमिका की एजेंसियों	पीआरआई सीबीओ-ग्राम में अभिसरण / सरकार राज्य/पंचायत भूमिका की एसआरएलएम को स्पष्ट करना	जीपी स्तर पर अभिसरण और सहभागिता शासन को सक्षम करने के लिए मजबूत संस्थागत संरचना को कैसे रखा जाए मूलभूत मांगों के एकीकरण के लिए एजेंसी के रूप में सीबीओ नेटवर्क कैसे बनाया जाए अभिसरण के लिए संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित करना	पीआरआई को मजबूत और बनाए रखने में मदद करने के लिए समुदाय को पोषित करने हेतु प्रतिभागी पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत हो जाते हैं प्रभावी ग्रामीण शासन के लिए महिला संगठन और पीआरआई की भागीदारी को कैसे मजबूत किया जा सकता है
सत्र 6: गरीबी न्यूनीकरण के लिए अभिसरण सक्षम करना	पीएई और ईएपी और जीपी गरीबी न्यूनीकरण योजना की पद्धति पर प्रतिभागियों को अभिमुख करना	जानकारी लेने डेटाबेस , लिए के करने तैयार सहभागिता उपकरण के रूप में पीएई का उपयोग अधिकार अभिगम	प्रतिभागी निम्नलिखित के बारे में जानेंगे: प्रत्येक एसएचजी द्वारा पीएई)सूक्ष्म योजना (निर्माण का

		योजना प्रत्येक वीओ द्वारा तैयार की गई एक लक्षित योजना है जीपी गरीबी न्यूनीकरण योजना जीपी के साथ साझेदारी में एसएचजी द्वारा तैयार की गई एक व्यापक मांग योजना है	वीओ द्वारा ईएपी योजना का निर्माण वीओ द्वारा जीपी गरीबी न्यूनीकरण की योजनाओं का निर्माण जीपीडीपी के साथ जीपी 2 आरपी योजनाओं का एकीकरण
सत्र 7: पीआरआई सीबीओ-अभिसरण-परियोजना	पीआरआई सीबीओ-के करने लागू को अभिसरण दृष्टिकोण गए अपनाए लिए को प्रस्तुत करना केएस एनआरओ-परियोजना की परिणाम संरचना को स्पष्ट करना केएस एनआरओ-लक्ष्य के परियोजना	एसएचजी को बढ़ावा देने और संस्था निर्माण के लिए केएस एनआरओ-परियोजना का अवलोकन प्रदान करना सीबीओ नेटवर्क के साथ पंचायत द्वारा बेहतर भागीदारी योजना की सुविधा	प्रतिभागियों को केएस-अभिसरण एनआरओ परियोजना का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य मिलेगा ग्राम पंचायत की गरीबी न्यूनीकरण योजना तैयार करने में वीओ और एसएचजी की भूमिका पर स्पष्ट जानकारी
सत्र 8: पीआरआई सीबीओ-अभिसरण का अपेक्षित निर्गम और परिणाम	आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में वीओ / साथ के एसएचजी को पंचायत करके साझेदारी है मिलता कैसे लाभ, समझाएं	पीआरआई सीबीओ-रूपांतरण का अपेक्षित निर्गम और परिणाम	पीआरआई सीबीओ-और आउटपुट के हस्तक्षेप में बारे के परिणामों प्रतिभागी अवगत होंगे पीआरआई सीबीओ-की कार्यक्रमों अभिसरण और योजना बेहतर पंचायतों में कार्यान्वयन , करेगा कैसे मदद की मूल्यांकन इसका

सत्र 1:

प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अभिसरण

स्वागत और उद्घाटन:

- आयोजक प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं और दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं और उन्हें पीआरआई-सीबीओ अभिसरण पर उन्मुख करते हैं
- प्रशिक्षण सुविधाप्रदाता कार्यक्रम के उद्देश्यों को सूचित करते हैं और प्रशिक्षण सुविधाप्रदाता के साथ-साथ प्रतिभागियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करते हैं

सत्र उद्देश्य:

- प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण पद्धति की प्रतिभागियों को जानकारी देना
- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना स्पष्ट करना
- प्रशिक्षण सुविधाकर्त्ताओं और प्रतिभागियों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों पर जानकारी प्रदान करना
- प्रत्येक प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से प्रमुख मुद्दों की स्थापना करना

सुगम पूर्वाभ्यास पद्धति:

इस सत्र को सुगम पूर्वाभ्यास सत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई मानक सुगम पूर्वाभ्यास पद्धति हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। सुगम पूर्वाभ्यास ऐसी पद्धतियाँ हैं जो अवरोध, संकोच को तोड़ने और एक दूसरे के साथ समूह के सदस्यों की बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद करती हैं। ये मित्रता, अनौपचारिकता और पारस्परिक स्वीकृति का वातावरण बनाने में मदद करती हैं।

सत्र सामग्री-

1.1 नियमावली की संरचना और सामग्री: यह प्रशिक्षण नियमावली पीआरआई-सीबीओ अभिसरण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण सुविधा देने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार की गई है। नियमावली क्षमता निर्माण और निर्वाचित प्रतिनिधियों, पीआर अधिकारियों, सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों, एसएचजी सदस्यों और अन्य लोगों के प्रशिक्षण के लिए मूल

सामग्री प्रस्तुत करती है। स्व-सहायता समूह और उनके संघों जैसे गरीब संस्थान और अन्य समुदाय आधारित संगठनों को कैसे उनके मांगों, अधिकार तथा हक तक पहुँचने में सशक्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्व-सहायता समूहों और पंचायतों के संघों के बीच संगठित अंतराफलक के विकास की सुविधा देना है। नियमावली पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के उद्देश्यों, तर्क और सिद्धांत को रेखांकित करता है जो गरीबों के लिए स्थान, विचार और संसाधन प्रदान करता है और बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करता है। नियमावली हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विषय वस्तु की व्यापक समझ विकसित करने के लिए संसाधन सामग्री प्रदान करता है। नियमावली में आठ विषय / सत्र शामिल हैं जो प्रशिक्षण के दो दिन में पूरे किए जाएंगे। सत्रवार सामग्री शामिल है।

सत्र 1: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अभिविन्यास

सत्र 2: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण की प्रस्तावना

सत्र 3: सीबीओ और ग्राम विकास में उनकी भूमिका

सत्र 4: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण

सत्र 5: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में भिन्नताओं की भूमिका

सत्र 6: गरीबी में न्यूनीकरण के लिए अभिसरण सक्षम करना

सत्र 7: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना-

सत्र 8: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण का अपेक्षित निर्गम और परिणाम

1.2 प्रशिक्षण सुविधा के लिए दिशानिर्देश: प्रशिक्षण सुविधाकर्ता सभी पीआर-सीबीओ अभिसरण से संबंधित गतिविधियों को हितधारकों को प्रशिक्षण देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ... सुविधाकर्ताओं को निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए

1. कार्यक्रम में प्रशिक्षण पद्धति अनिवार्य रूप से सहभागी और संवादात्मक होगी, जिसमें विभिन्न तरीकों जैसे संवादात्मक व्याख्यान, समूह कार्य, विचार मंथन, अनुभव साझा करना, भूमिका निर्वहन, फ्लिप चार्ट, अभ्यास और मामला अध्ययन आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण सुविधाकर्ता को उपयुक्त कोई अन्य पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है।
2. प्रशिक्षण सुविधाकर्ताओं से संबंधित राज्य के लिए विशिष्ट विषय आधारित सत्र तैयार करने के लिए इस सामग्री का उपयोग करने की उम्मीद है
3. प्रशिक्षक को प्रत्येक विषय में सामग्री के आधार पर अपने स्वयं के पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण, फ्लिपचार्ट या अन्य ऑडियो-विजुअल समर्थन विज्ञापन तैयार करना चाहिए।

4. जीपीडीपी तैयार करने में पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के महत्व और तत्वों को पहचानें। अवधारणाओं को चित्रित करने के लिए वास्तविक मामलों को प्रदान करने के लिए ठोस उदाहरण, परियोजना मूल्यांकन आदि का उपयोग करें।
5. प्रत्येक सत्र से पहले, प्रशिक्षण सुविधाकर्ता सत्र के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक सभी प्रशिक्षण साधन और सामग्री के साथ-साथ वितरण किए जाने के लिए तैयार सभी सामग्री अपने पास रखेगा।
6. सुविधाकर्ता, विषय को कवर करने वाली एक संक्षिप्त प्रस्तुति दे सकता है और फिर चर्चा के लिए सत्र चला सकता है। चर्चा और विषय पर अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए अनुभव साझा करने हेतु कम से कम एक-तिहाई समय देना चाहिए।
7. स्थानीय जरूरतों और समय के अनुसार सामग्री में मामूली परिवर्तन / नवपरिवर्तन किए जा सकते हैं।
8. पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के मौलिक सिद्धांतों, पद्धतियों और तकनीकों के कौशल और समझ बढ़ाने को प्रोत्साहित करें।
9. प्रत्येक सत्र के बाद, किस पर बेहतर कार्य किया जा सकता है, किसे सुधारा जा सकता है और कौनसे सुधारात्मक कार्य किए जा सकते हैं इन बातों पर प्रशिक्षक को प्रतिभागियों का फीडबैक लेना चाहिए।

1.3 प्रतिभागियों के लिए दिशानिर्देश

1. प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और क्षेत्र से संबंधित उनके सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभवों को साझा करना होगा। यह बेहतर रणनीतियों के निर्माण में मदद करेगा।
2. प्रतिभागियों को सत्र की प्रासंगिकता को समझने और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए।
3. उन्हें क्षेत्र की सामाजिक स्थितियों के बारे में सत्रों में उठाए गए प्रश्नों को एक साथ जोड़ने में सक्षम होना चाहिए।
4. प्रतिभागियों को सामान्य चर्चा के लिए अपनी चिंताओं और संदेहों को साझा करने में आगे आना चाहिए। इससे उन्हें स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वास्तविक जीवन के मुद्दों के लिए व्यावहारिक समाधान की पहचान की जाएगी।

सत्र 2:

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण की प्रस्तावना

सत्र के उद्देश्य:

- पीआरआई के संवैधानिक अधिदेश का विवरण देना
- ☐ गरीबों के संस्थान एसएचजी की अवधारणाओं को स्पष्ट करना
- पंचायतों के समन्वयन में कार्य करने के लिए डीआई-एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी को उपलब्ध लोकतांत्रिक स्थान
- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण की अवधारणा और इसके सुदृढीकरण की आवश्यकता

सत्र का संक्षेप:

- ☐ भारत के संविधान ने पंचायती राज संस्थानों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी सौंपी है। इन कार्यों को करने के लिए, पीआरआई को समुदाय आधारित संगठनों, खासकर गरीबों के साथ काम करने की ज़रूरत है। पंचायत और एसएचजी के बीच एक प्रभावी और कार्यात्मक कार्य संबंध की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए डीआई-एनआरएलएम पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के लिए संरचना प्रदान करता है।
- मनरेगा के तहत आवश्यक गहन सहभागिता योजना पद्धति ने श्रम बजट की तैयारी में एसएचजी और उसके संघों के लिए मध्यवर्ती भूमिका निभायी। यह एसएचजी और ग्राम पंचायतों के बीच एक परिचालन संयोजन लाया है
- ☐ पीआरआई-सीबीओ अभिसरण का उपयोग बहिष्करण का समाधान करने, भागीदारी को सक्षम करने, अधिकारों का दावा करने और समानता को समझने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है।
- ☐ पीआरआई-सीबीओ अभिसरण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के साथ काम करने के लिए एसएचजी नेटवर्क की क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि उनके सम्यक् अधिकारों और हक तक पहुँच बढ़ाकर और स्थानीय लोकतांत्रिक शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी मध्यवर्ती से उनके जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें।

समूह कार्य: प्रतिभागियों को एक विषय पर समूह रिपोर्ट तैयार करने के लिए समूहों में विभाजित किया जा सकता है और इसे प्रशिक्षण सुविधा देने वालों के सामने प्रस्तुत किया जाना होगा। यह सुविधाकर्त्ताओं और प्रतिभागियों को अध्ययन हस्तांतरण की सीमा का मूल्यांकन करने में सक्षम करेगा।

सत्र सामग्री

2.1 पीआरआई के संवैधानिक अधिदेश: भारत के संविधान ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को अनुसूची XI में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी सौंपी है। स्थानीय सरकार के रूप में जीपी स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं और गरीब और हाशियाकृत लोगों की असुरक्षितता का समाधान करते हैं। यह केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल और जिम्मेदार उपयोग के माध्यम सुविचारित योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा हासिल किया जा सकता है। इसलिए, जीपी की मुख्य कार्यप्रणाली के भाग के रूप में एक कुशल और मजबूत योजना प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। जीपी विकास योजना का उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल खाना जरूरी है और इस तरह इसे निष्पक्ष, समावेशी, पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना है ...

2.2 गरीबों के संस्थान: स्व-सहायता समूह (एसएचजी) गांवों में गरीबों के मजबूत संस्थान हैं जो गरीबों के लिए स्थान, विचार और संसाधन प्रदान करते हैं और बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करते हैं। ये संस्थान गरीबों को सशक्त बनाते हैं और ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रसार, उत्पादन, सामूहिकीकरण और वाणिज्य के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार ने समुदाय आधारित संगठनों के आसपास व्याप्त गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति को लागू करने के लिए जून 2010 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीआई-एनआरएलएम) की स्थापना की। डीआई-एनआरएलएम गरीबों के सार्वभौमिक समावेश पर केंद्रित है, जो सहभागिता प्रक्रियाओं के माध्यम से जाना जाता है और स्थायी आजीविका और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए क्रेडिट और एक्सेस सेवाओं तक पहुंच के लिए समर्थन बढ़ाता है।

2.3 स्वयं सहायता समूहों के लिए लोकतांत्रिक स्थान: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सुपुर्दगी की गुणवत्ता को बदलने के लिए लाभकारी रूप से रखा गया है। ये एसएचजी महिलाओं और उनके परिवारों को संगठित करने और उन्हें ग्रामसभा में लाने की स्थिति में हैं। एसएचजी स्थानीय विकास के मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जो जीपी के लिए किए गए स्थिति विश्लेषण पर अधिक ध्यान देंगे। एसएचजी द्वारा गरीबी की समझ उन्हें पंचायत का ध्यान आकर्षित करने और उनके

अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करती है। हितधारकों के रूप में वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र जैसे गरीबों की सेवा करने के लिए संस्थान और मध्याह्न भोजन, आईसीडीएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इत्यादि जैसे सामाजिक विकास के कार्यक्रम उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं में ग्राम पंचायतों और एसएचजी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भ के लिए अनुलग्नक -1 में दिया गया है।

2.4 पीआरआई-सीबीओ अनुबंध: देश भर में एसएचजी कार्यक्रम का बल श्रिफ्ट और क्रेडिट पर रहा है, वित्तीय अनुशासन विकसित करता है और आजीविका विकल्पों में सुधार करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सुपुर्दगी की गुणवत्ता को बदलने के लिए लाभप्रद रूप से रखा गया है। मनरेगा के तहत आवश्यक गहन सहभागिता योजना पद्धति (आईपीपीई) ने श्रम बजट की तैयारी में एसएचजी और उसके संघों को मुख्य भूमिका दी है। एमजीएनआरआईएस के तहत बड़े पैमाने पर कार्य पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध है, आईआईपीपीई, एसएचजी और ग्राम पंचायतों के बीच एक परिचालन संयोजन लाया है ... पंचायत और एसएचजी के बीच प्रभावी अभिसरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, डीआई-एनआरएलएम ढांचा पीआरआई-सीबीओ अभिसरण प्रदान करता है। पीआरआई-सीबीओ अभिसरण का उपयोग बहिष्कार का समाधान करने, भागीदारी बढ़ाने, अधिकारों का दावा करने और समानता को साकार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है।

2.5 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता: सीबीओ और पीआरआई में एक मूलभूत संबंध विकसित करने के माध्यम से, कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण के साथ-साथ अधिकारों तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना संभव है। पीआरआई और सीबीओ में तालमेल सुनिश्चित किया है ताकि सशक्त समुदाय अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पंचायत अपनी संवैधानिक भूमिका और जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके।

अभिसरण क्या है?

अभिसरण सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा संसाधनों, उद्देश्यों और विशेषज्ञता का संरेखण है। अभिसरण में गरीब से गरीब को सशक्त करना साथ के सरकारों स्थानीय और समानता जेंडर, स की लोगोहभागिता और भागीदारी को सम्मिलित करने पर ध्यान दिया जाता है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है। अभिसरण दृष्टिकोण का विकास चुनौतियों को संबोधित करने में एक विशेष महत्व है क्योंकि इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, सामुदायिक नेटवर्कों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग के माध्यम से लाया जाता है।

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण क्या है?

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण दृष्टिकोण इस पर आधारित रहता है कि यदि सीबीओ और पीआरआई जैसे गरीबों के संस्थान गांव के विकास के लिए सहयोग करते हैं, कमजोर और गरीबों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा में काफी वृद्धि हो सकती है।

समूह कार्य प्रश्न मॉडल लिए के करने साझा अनुभव /

कक चर्चा पर जिम्मेदारियों कार्यात्मक उनकी में राज्यों संबंधित और बदलाव में संरचना की पीआरआई (रना
ख अधिनियम पीआर राज्य (के तहत आबंटित ग्राम सभा की जिम्मेदारियां क्या हैं
गक चर्चा पर पहलों साझेदारी एसएचजी-पंचायत ग्राम में राज्यों संबंधित (रना
घहै क्या स्तर वर्तमान का समितियों विकास विभिन्न में गांवों और भागीदारी की महिलाओं में सभा ग्राम (

सत्र 3:

समुदाय आधारित संगठन और ग्राम विकास में उनकी भूमिका

सत्र के उद्देश्य

- ☐ सीबीओ क्या हैं स्पष्ट करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न प्रकार के सीबीओ पर चर्चा करना
- ☐ ग्रामीण विकास में सीबीओ क्या भूमिका निभा सकते हैं इसे स्पष्ट करना

सत्र का संक्षेप:

- ☐ स्व-सहायता समूह उन लोगों के समूह हैं जो कई पहलुओं में समानता साझा करते हैं; लिंग, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्थितियां आदि। महिला स्व-सहायता समूहों के मामले में, एकरूपता एक विस्तारित पारिवारिक स्थान बनाती है जहां वे अपने परिवार के मामलों को भी साझा कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ सरल मुद्दों या विषयों को साझा करते हुए, एसएचजी के सदस्य परिवर्तन शुरू कर देते हैं और अपने विचारों को योजनाओं और कार्यों में बदल देते हैं।
- ☐ सीबीओ उपलब्ध होने की कई परिभाषाएं उपलब्ध हैं, लेकिन एक सरल व्यक्ति उन्हें एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित लोगों के सभी संगठनों या समूहों के रूप में परिभाषित करता है, इसके सदस्यों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन किया जाता है, समूह पहचान होती है और धार्मिक या राजनीतिक समूह से संबद्ध नहीं होता। पीआरआई के संदर्भ में, सीबीओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत विकसित एसएचजी के संघों को संदर्भित करता है
- ☐ पीआरआई-सीबीओ अभिसरण मॉडल पीआरआई और सीबीओ की संरचना और भूमिका पर लाभ उठाता है, और स्थानीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उनके बीच तालमेल बनाता है

सत्र सामग्री-

3.1 सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ): समुदाय आधारित संगठन अपने सदस्यों के हित के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ लोगों के लिए बनाए गए छोटे संगठन हैं। वे ज्यादातर अनौपचारिक निकाय होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और संस्थान के प्रत्येक सदस्य की इसमें हिस्सेदारी होती है। जबकि सीबीओ वास्तव में

समुदाय आधारित हैं, वे न तो निर्वाचित हैं और न ही समुदाय के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे संगठनों के केवल नेता ही अपने सदस्यों के लिए उत्तरदायी रहते हैं। संगठन की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने से आटिमयता का बोध होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सीबीओ मौजूद हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

3.2 स्व-सहायता समूह और डीआई-एनआरएलएम: 10-15 संख्या में गठित एसएचजी महिलाओं का समूह है - और ऐसे समूहों की सामान्य गतिविधि थिफ्ट और क्रेडिट है। ऐसे समूहों के सदस्यों को अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाना अनिवार्य है। थिफ्ट और क्रेडिट गतिविधि के अलावा, एसएचजी सूक्ष्म उद्यम चलाते हैं। भारत सरकार ने जून 2010 में समुदाय आधारित संस्थानों के आसपास चल रहे गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीआई-एनआरएलएम) की स्थापना की। डीआई-एनआरएलएम का मिशन गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार और कुशल मजदूरी के रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए गरीबी को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के मजबूत मूलभूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से एक स्थायी आधार पर उनकी आय में सहायनीय वृद्धि होती है। डीआई-एनआरएलएम ढांचा पंचायतों को बीपीएल परिवारों को एसएचजी में पहचानने और संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उनके प्रभावी कामकाज के लिए एसएचजी को सुविधा मिलती है, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं में उनकी प्राथमिक मांगों को वित्तीय आबंटन में शामिल किया जाता है।

3.3 उपयोगकर्ता समूह: कई सार्वजनिक संपत्तियों का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अक्सर ऐसी संपत्तियों के उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पीने के पानी की सुविधा के रखरखाव के लिए या सिंचाई कुओं के प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता संघ हो सकता है। ऐसी संपत्तियों का उपयोग करने वाले सभी सदस्य ऐसे समूहों के सदस्य बन जाते हैं। उनमें से सभी संपत्तियों में हिस्सेदारी है। एक बार गठित होने के बाद, ऐसे समूह संचालन और प्रबंधन के लिए अक्सर अपने आंतरिक नियम तैयार करते हैं, संचालन और रखरखाव व्यय को पूरा करने के लिए शुल्क लिया जाता है। इस तरह के शुल्क का स्वेच्छा से सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाता है उपयोगकर्ता के समूह, सार्वजनिक संपत्ति के सामुदायिक रखरखाव में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं।

3.4 युवा क्लब: युवा क्लब युवा लोगों का संगठन हैं। ज्यादातर मामलों में, युवा क्लब युवा लोगों की मनोरंजक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। आंतरिक या बाहरी खेल का संगठन उनकी प्रमुख

गतिविधि है। लेकिन, वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी शामिल होते हैं, जैसे साक्षरता केंद्र चलाना, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का आयोजन करना, समुदाय त्यौहार आदि आयोजित करना आदि।

3.5 महिला मंडल: महिला मंडल महिलाओं के लिए सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए बेहतर मंच हैं। ऐसे संगठन महिलाओं की सामाजिक जरूरतों को अपने परिवार से बाहर की महिलाओं से बातचीत करने के लिए काम करते हैं। वे विभिन्न विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए महिलाओं को मंच भी प्रदान करते हैं, जैसे साक्षरता, सामाजिक समस्याओं से अवगत होना, कौशल उन्नयन कार्यक्रमों में भागीदारी आदि।

3.6 लाभार्थी समितियां: लाभार्थी समितियां सीबीओ भी हैं, लेकिन मामूली फर्क है। गतिविधियों के लाभ स्थानीय समुदाय से संबंधित है, लेकिन समिति के सदस्यों की गतिविधियों पर उनकी पकड़ कमजोर है। समिति के सदस्य लाभार्थियों की तरफ से कार्य करते हैं। यदि लाभार्थी सतर्क नहीं है, तो समितियों के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की संभावना हो सकती है।

3.7 संयुक्त वन प्रबंधन समूह: वन संपत्ति सरकार की है लेकिन जंगल के आसपास के स्थानीय समुदाय में इसकी हिस्सेदारी है, क्योंकि वे शाखाएं, टहनियां और अन्य मामूली वन उपज इकट्ठा करते हैं। चोरी, वृक्षों की अनधिकृत कटाई और हस्तक्षेप से सुरक्षा, सरकार के लिए खतरनाक समस्याएँ थी। वन विभाग का कार्य वन के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का है। इस उद्देश्य के लिए, स्थानीय समुदाय की सदस्यता के साथ संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) समूह की स्थापना की गई। उन्हें जंगलों के प्रबंधन की पर्याप्त जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बदले में, समूह के सदस्यों को वन संपत्ति की आय का एक हिस्सा साझा करने की अनुमति है।

3.8 ग्राम विकास में सीबीओ की भूमिका: विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग स्वयं परिवर्तन एजेंटों की भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में, विकास लोगों द्वारा किए गए गतिविधियों का नतीजा है। लोकतंत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी उनके व्यक्तिगत वोट को देने के साथ खत्म नहीं होती है, लेकिन वे खुद को अपने विकास के लिए प्रासंगिक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के बोझ को साझा करने में सीधे शामिल होते हैं। विकास में सरकार की भूमिका केवल एक सुविधाकर्ता के रूप में है। सीबीओ सरकारी संस्थान के प्रयास का समर्थन करते हैं और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीबीओ की सक्रिय भागीदारी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण, स्वच्छता, संचालन और जल आपूर्ति योजनाओं, ग्रिफ्ट और क्रेडिट कार्यक्रम तथा सूक्ष्म उद्यम आदि के रख-रखाव जैसे क्षेत्रों में बेहतर परिणाम ला सकती है। इस

प्रकार विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए सहभागिता, पीआरआई की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में सीबीओ को बढ़ावा देने और शामिल करने की जिम्मेदारी है।

एसएचजी और एसएचजी फेडरेशन की भूमिका

इंटरफेस प्रदान करना: संघ समुदाय, ग्राम पंचायत और अन्य विकास संगठनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर सकता है। कुछ मामलों में, एसएचजी स्वयं आवश्यक परिवर्तन को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि, वे समस्याओं की पहचान करने, मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और उचित नीति शिफ्ट को बढ़ावा देने की स्थिति में हैं। वे सरकार और अन्य संस्थानों को उनकी मांगों को पहचानने और उनके अधिकारों तक पहुंचने पर दबाव डाल सकते हैं। एक संघ मौजूदा संरचनाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक साथ-सह में जोड़ने को व्यक्तियों में स्थापना की रूपों वैकल्पिक के गतिविधियों कायता प्रदान कर सकता है।

नेतृत्व गुणों का विस्तार: सीबीओ के संघ स्तर पर नेतृत्व गुणों का विस्तार देखा जा सकता है। एसएचजी के सदस्य, संघ के एक हिस्से के रूप में अपने नेतृत्व के गुणों का विस्तार कर सकते हैं जिसमें वे कई एसएचजी और समुदाय के लाभ की दिशा में काम करते हैं।

ज्ञान का विस्तार: वे पंचायत के साथ बहुत करीब से काम भी करते हैं। इसके माध्यम से, उन्हें पंचायत की भूमिका, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी भी मिलती है। इससे उन्हें उचित धारक की क्षमता और महिला समुदाय के नेता में अपने अधिकारों की मांग करने में मदद मिलती है। समूहों से शेयरिंग और सीखने के माध्यम से समुदाय का ज्ञान बढ़ाया जाता है।

सामाजिक न्याय और समता को बढ़ावा देना: सामाजिक बुराइयों, भेदभाव और सौहार्द की दिशा में काम करना

निगरानी: संघ, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, लाइन विभाग आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर समुदाय की मांगों की निगरानी और अनुपालन कर सकता है।

समूह कार्य प्रश्न मॉडल लिए के करने साझा अनुभव /

- विभिन्न राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम ने कैसे स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार तक पहुंचने में गरीब परिवारों को सक्षम करके गरीबी कम की है।
- सीबीओ की सक्रिय भागीदारी कैसे आईसीडीएस, प्राथमिक शिक्षा और एसबीए जैसी पुरानी परिणाम प्रमुख आरडी योजनाएं ला सकती है।

सत्र 4:

पीआरआई - सीबीओ अभिसरण

सत्र के उद्देश्य:

- अभिसरण के लिए आवश्यकता और अवसर
- पीआरआईआरएचजी अभिसरण के उद्देश्य
- □ अभिसरण के औचित्य और सिद्धांत
- □ क्षेत्र जहां पीआरआई-सीबीओ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं

सत्र का संक्षेप:

- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय आधारित संगठन पंचायती राज संस्थानों के साथ निर्बाध रूप से काम करते हैं
- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण दृष्टिकोण इस पर आधारित है कि अगर सीबीओ और पीआरआई जैसे गरीबों के संस्थान गांव के विकास के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं ...
- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण पंचायत और एसएचजी नेटवर्क को गरीबों की पहुंच को मजबूत करने और उन्नत सेवा सुपुर्दगी के लिए स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। इसे प्राप्त करने के लिए, स्थानीय स्त्रोत समूह की क्षमता को पीआरआई और सीबीओ के अभिसरण के कार्य हेतु विकसित करने की आवश्यकता है।

समूह कार्य :

- प्रतिभागियों को विभिन्न छोटे समूहों में विभाजित किया जा सकता है और विशिष्ट कार्यों को उन्हें सौंपा जा सकता है। एक समूह के गठन के दौरान, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समूह शिक्षा, अनुभव और प्रतिभागियों के मामले में मिश्रित समूह हो। समूह एक समूह नेता का चयन कर सकता है जो समूह समन्वयक की भूमिका निभाएगा। समूह संकाय के रूप में समूहों के लिए आंतरिक संकाय सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। समूहों को पीआरआई-सीबीओ को अभिसरण से संबंधित एक विशिष्ट विषय सौंपा जा सकता है जिस पर वे महत्वपूर्ण चर्चा और समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सत्र सामग्री-

4.1 अभिसरण के लिए आवश्यकता और अवसर: ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में समन्वित निर्धनता उन्मूलन योजना के माध्यम से गरीब और सीमान्तीकृत लोगों और उनकी आजीविका के सुअवसर द्वारा उनकी समस्या का समाधान करने के महत्वपूर्ण घटक को शामिल करता है। लोकतांत्रिकरण और गरीबों की भागीदारी योजना की आवश्यक शर्तें हैं, जिन्हें पीआरआई और सीबीओ के बीच अभिसरण द्वारा हासिल किया

जा सकता है। एसएचजी और उनके संघ, गरीबों के संस्थानों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएचजी को ग्राम सभा और पंचायतों के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेने, समुदाय आधारित निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करने और ग्राम पंचायतों को उनके विकास पहल और योजना अभ्यास में समर्थन देने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। डीएआर-एनआरएलएम पर विचार किया गया है कि अधिकारों, हकों और उनके सदस्यों के लिए सरकार की योजनाओं तक पहुँचने और जीपीडीपी की तैयारी में पंचायतों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए एसएचजी और उनके गांव स्तरीय संघ, ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर काम करें - आवास और ग्राम पंचायत स्तर पर एसएचजी के साथ अभिसरण महत्वपूर्ण रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों के समुदाय के स्वामित्व को बढ़ाता है

4.2 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के उद्देश्य: निम्नलिखित पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के उद्देश्य हैं

1. गरीबों को उनके अधिकारों और हकों को जानने, मांग करने और उन तक पहुँचने के लिए सशक्त करना।
2. स्थानीय विकास-समुदाय में समुदाय के गरीब और कमजोर वर्गों को शामिल करें और उन्हें इससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम करें।
3. ग्राम पंचायत को उत्तरदायी और उत्तरदायी बनाने वाले स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करें।
4. स्थानीय स्तर के विकास को सक्रिय करें और इसे सहभागी एवं समावेशी बनाएं।
5. निर्धन केंद्रित कार्यक्रमों की क्षमता और पहुंच में वृद्धि
6. सामुदायिक संगठन नेटवर्क के साथ पंचायत द्वारा बेहतर भागीदारी योजना
7. स्थानीय सरकारी संस्थानों को सुदृढ़ और सतत बनाए रखने में मदद के लिए समुदाय को सशक्त करना
8. स्थानीय स्व-शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ बनाना
9. पंचायती राज प्रणाली को समाज, विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाएं
10. अभिसरण के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सामुदायिक संस्थानों और स्थानीय सरकारों के साथ काम करने के हेतु सामुदायिक व्यावसायिकों का कैडर तैयार करने में सहायता करें

4.3 अभिसरण का औचित्य

1. एसएचजी और उनके संघ लोकतंत्र के कार्यकलापों को सीखेंगे और ग्राम सभा में सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानदंडों को विकसित करने में उनकी मदद करेंगे, जो बदले में सबके हित में सार्वजनिक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है।
2. समुदाय को अपने अधिकारों, हक के बारे में जागरूक करें और उन्हें अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएं।

3. एसएचजी को स्थानीय योजना, विशेष रूप से काम और आजीविका, बुनियादी सेवाओं और विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से मूलभूत आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने में सहायता करें
4. समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना और समान शर्तों पर गरीबों के साथ निकटता से जुड़ना लोकतंत्र और ग्राम पंचायत की वैधता को मजबूत करता है
5. ग्राम पंचायत ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत एसएचजी नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, खासतौर से स्थानीय स्तर की योजना बनाने में सुधार, आउटरीच, विस्तार और सेवा वितरण के साथ-साथ फ्रीड-बैंक के लिए भी उनका उपयोग करें।

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण मॉडल

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण मॉडल पीआरआई और सीबीओ की संरचना और भूमिका का लाभ उठाता है, और स्थानीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मिलकर काम करने के लिए उनके बीच तालमेल बनाता है। ये निकाय निम्नलिखित तरीकों में मिलकर काम कर सकते हैं:

1. पीआरआई कर सकते हैं:

सीबीओ के माध्यम से अधिकारों के बारे में समुदायों में जागरूकता पैदा करें।

लक्षित समुदायों को हक देने में विभागों को प्रभावित करें।

सरकारी योजना के लक्षित लाभार्थियों की पहचान के लिए सीबीओ के साथ काम करें।

सीबीओ कर सकते हैं:

ग्राम सभा में प्रभावी रूप से भाग लेते हैं और अपने अधिकारों और हकों के लिए लड़ कर सकते हैं

स्थानीय जरूरतों और मुद्दों का आकलन करें और जीपीडीपी तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं

4.4 अभिसरण में अंतर्निहित सिद्धांत: पंचायतों और एसएचजी के बीच निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत अभिसरण हैं।

1. स्थानीय स्वयं सरकार के संस्थानों के रूप में पंचायतों की स्वीकृति।
2. स्पष्ट अधिकारों और कार्यों के साथ गरीबों के स्वायत्त संस्थानों के रूप में एसएचजी और उनके संघों की शिनाख्त किसी भी परिस्थिति में पंचायतों द्वारा उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

3. पंचायत और एसएचजी दोनों को जानकारी साझा करने और परामर्श एवं संवाद के माध्यम से कार्यों, जिम्मेदारियों और एक दूसरे की गतिविधियों के विवरण जानने का एक सही अधिकार है।
4. मानदंडों और मापदंडों के आधार पर पारदर्शी और नियम आधारित प्रणाली पर एक साथ कार्य करना अनिवार्य है।
5. भागीदारी को कार्यात्मक और सुचारू बनाने के लिए, संरचनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है - संरचनात्मक संबंध, वित्तीय संबंध, और विकास संबंध आदि।

4.4 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के क्षेत्र: ग्राम पंचायत और एसएचजी / एसएचजी संघ निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं -

1. ग्राम पंचायत पीआरआई की वार्षिक योजनाओं / गतिविधियों में एसएचजी और उनके संघों की प्राथमिक मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन और एसएचजी नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों और अधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करके सामाजिक संगठन, संस्थागत निर्माण और ग्राम सभा में गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी) एवं उसके अनुमोदन से सुविधा और सहायता प्रदान कर सकेंगे।
2. एसएचजी और उनके संघ अपने सदस्यों को उनकी मांगों और जरूरतों को प्रस्तुत करने के लिए ग्रामसभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। एसएचजी समुदाय की जरूरतों और मांगों पर चर्चा कर सकते हैं और ग्रामसभा से सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं। एसएचजी संघों को जीपी की कार्यात्मक समितियों (यदि वे सदस्य / आमंत्रित हैं) में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रक्रिया और जीपी के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सामुदायिक निगरानी में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है।
3. सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और गरीबी मुक्त जीपी के लिए योजना गरीब और सीमान्तीकृत लोगों और उनकी आजीविका के अवसरों की कमियों को दूर करने वाले घटक के साथ एक स्पष्ट एकीकृत निर्धनता उन्मूलन योजना की आवश्यकता है। इसके लिए, संघों को एसईसीसी डेटा, गरीबी और एंटाइटेल्मेंट आदि के सहभागिता आकलन के लिए तैयार समेकन की आवश्यकता है जो सदस्यों की सामाजिक विकास आवश्यकताओं को व्यक्तिगत / सामूहिक रूप से पूरा करे। इस एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, एसएचजी संघों को विभिन्न परियोजनाओं, कार्यात्मक समितियों और जीपीडीपी प्रक्रिया के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :-

क) पर्यावरण निर्माण, डेटा संग्रह, स्थिति विश्लेषण और दूरदर्शिता

- ख) संसाधन आवरण की पहचान
- ग) ग्राम सभा में भागीदारी
- घ) परियोजना
- ङ) परियोजनाओं का कार्यान्वयन
- च) समुदाय आधारित निगरानी

जीपीडीपी में एसएचजी शामिल करना

एसएचजीएस औपचारिक रूप से नीचे दिए गए अनुसार जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है:

1. एसईसीसी डेटा और सहभागी आकलन के आधार पर उनकी गरीबी और आजीविका स्तर पर चर्चा करें।
2. ग्राम पंचायत में गरीबी का एक प्रावधान विकसित करना और मुख्य कारणों और समाधानों को इंगित करने वाला एक मैट्रिक्स विकसित कर सकता है।
3. ग्राम पंचायत के स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण हेतु गरीबी उन्मूलन योजना तैयार करें।
4. जीपीडीपी के लागतहीन विकास घटकों में सक्रिय रूप से शामिल हो, जैसे पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, विभिन्न जन सेवाओं के वितरण में अंतिम लिंक प्रदान करना और सामाजिक बुराइयों को मिटाना

समूह कार्य / अनुभव साझा करने के लिए मॉडल प्रश्न

- चर्चा करें कि ग्राम पंचायत कैसे सामाजिक संगठन और गरीबों की आवश्यकता की सहभागी अभिनिर्धारण में वीओ / एसएचजी को सुविधा और समर्थन दे सकता है।
- कौन से ऐसे क्षेत्र / गतिविधियां / हस्तक्षेप हैं जहां गांव में लागतहीन विकास संभव है।
- समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए पीआर निर्वाचित प्रतिनिधी क्या भूमिका निभा सकते हैं।
- एसएचजी योजना और उनके संघ, गरीबों के संस्थान आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हस्तक्षेप में ग्राम पंचायत का समर्थन कर सकते हैं

सत्र 5:

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां

सत्र के उद्देश्य:

- भूमिका स्पष्ट करें
 - पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में ग्राम पंचायत
 - पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में राज्य सरकार
 - पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में एसआरएलएम

सत्र का सार

- ग्राम पंचायतों को प्रमुख भूमिका का निर्वहन करना है:
 - गरीबों के सहभागी अभিনিर्धारण और उनके सामाजिक संगठन के आयोजन में वीओ / एसएचजी को सुविधा प्रदान करना और सहायता देना
 - सूचित भागीदारी के माध्यम से ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एसएचजी और उनके संघों को शामिल करना
 - जीपीडीपी के भाग स्वरूप निर्धनता उन्मूलन योजना तैयार करने के लिए एसएचजी को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए, एसएचजी की मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
- राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है:
 - ग्राम पंचायत स्तर विकास योजना के लिए योजना टीमों में एसएचजीएस से सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का सह-चयन करें जिसमें एमजीएनआईजीएस शामिल होंगे।
 - स्पष्ट मानदंडों के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा की सहायता करने में एसएचजी को औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपना
- इसी प्रकार एसआरएलएम को आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करके फेडरेशन / ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों / स्थानीय स्त्रोत समूहों के क्षमता विकास की आवश्यकता है

समूह कार्य :

- प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है जो एक विषय पर समूह रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा यह प्रशिक्षण सुविधाकर्त्ताओं के प्रस्तुत की जाएगी, जो रिपोर्ट पर टिप्पणी करेंगे। यह, प्रतिभागियों को जानकारी का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा।

सत्र सामग्री-

5.1 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में ग्राम पंचायत की भूमिका: ग्राम पंचायत निम्नलिखित गतिविधियों में एसएचजी की सुविधा और समर्थन कर सकती है

1. गरीबों का सहभागी अभिनिर्धारण, उनका सामाजिक संगठन और तत्पश्चात् एसएचजीएस और ग्राम संगठनों के रूप में संस्थागत निर्माण
2. जरूरतों और प्राथमिकताओं पर एसएचजी में पूर्व चर्चा के बाद सूचित भागीदारी के माध्यम से ग्राम सभा को सुदृढ़ करना।
3. स्थानीय स्तर की नियोजन प्रक्रिया में, विशिष्ट रूप से गरीबी न्यूनीकरण से संबंधित मामले
4. एसएचजी की मांगों को प्राथमिकता देते हुए जीपीडीपी के भाग के रूप में गरीबी न्यूनीकरण योजना तैयार करना
5. एमजीएनआरईजीएस के तहत काम मांगने वाले श्रमिकों की पहचान करना, श्रम बजट तैयार करना।
6. कुछ लागत मानदंडों पर मध्याह्न भोजन, प्रत्येक घर से कर संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पाइप से पेयजल आपूर्ति का संचालन और रखरखाव, ई-सेवाओं आदि जैसी सेवाओं की सुपुर्दगी।
7. एसएचजी संघों के कार्यालय के लिए जीपी कार्यालय के परिसर में एक अलग स्थान दें। इससे न केवल एसएचजी की दक्षता में वृद्धि होगी बल्कि पंचायतों के साथ उनकी बातचीत की गुणवत्ता में सुधार होगा।
8. एसएचजी को उनके आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक भूमि, तालाब और बाजार स्थान जैसे सामान्य संसाधन पाने में प्राथमिकता देना। इससे न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित होगा बल्कि ग्राम पंचायतों के अपने स्रोत राजस्व को भी बढ़ाएगा।
9. सुनिश्चित करें कि एसएचजी की स्वायत्तता सामान्य संसाधनों तक पहुंचने और सेवाओं के वितरण में प्राथमिकता के अनुसार प्राथमिकता के अनुसार संरक्षित है।
10. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति और अस्पताल समिति जैसी कार्यात्मक समितियों में संघ के नेताओं और उनके सदस्यों को सदस्यता दें।

11. शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग, हाथों से सफाई, बाल विवाह, बाल श्रम, महिलाओं की तस्करी आदि जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए एसएचजी की सामाजिक पूंजी का उपयोग करना।
12. जीपी स्तर पर अभिसरण गतिविधियों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष और जीपी एवं एसएचजी संघों के सदस्यों की अध्यक्षता वाली संयुक्त समितियां स्थापित करें।
13. महिला संघों को निर्धनों की सहभागी शिनाख्त तथा आजीविका एवं रोजगार मजदूरी आदि के लिए उपयुक्त कार्य की शिनाख्त तथा ग्राम सभा में इसकी स्वीकृति में सुविधा और समर्थन देना।
14. विशेषतया लक्षित समूहों तक व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण और विकासात्मक कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर जानकारी की प्रसार की पहुँच के लिए एसएचजी का उपयोग करना।
15. समुदाय आधारित मानिट्रिंग विशेषकर उचित विकास लक्ष्यों के विशेष संदर्भ में विकासात्मक हस्तक्षेप की सेवा सुपुर्दगी और कार्य के लिए एसएचजी का उपयोग
16. स्थानीय अनुबंध के रूप में सामुदायिक अनुबंध के माध्यम से एसएचजी और उनके संघों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारियां सौपना।
17. उचित उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने की स्वतंत्रता के साथ उपयोगिताओं और परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए एजेंसियों के रूप में एसएचजी का उपयोग करें।
18. एसएचजी के बीच से सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों (सीआरपीएस) को उचित पारिश्रमिक पर विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित करें।
19. एसएचजी और उनके संघ को (मछली तालाब, सार्वजनिक संपत्ति, बाजार अहाता आदि) पंचायत के संसाधन पट्टे पर देना।
20. एसआईजी को स्थिति विश्लेषण, दूरदर्शिता, परियोजनाकरण और महिला सभा को सक्रिय करने और आयोजन करने की सुविधा में भूमिका देना
21. पीआरआई की वार्षिक योजनाओं / गतिविधियों में एसएचजी और उनके संघ की प्राथमिक मांगों के लिए उपयुक्त वित्तीय आबंटन करें
22. प्रक्रियाओं के साथ-साथ परिणामों के लिए ग्राम पंचायत की योजनाओं और परियोजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी में एसएचजी / संघों को शामिल करें
23. पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, जहां ग्राम सभा को निर्णय लेने की शक्तियों के साथ अधिकार दिया गया है, एसएचजी पीईएसए अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को साकार करने में शामिल हो सकती हैं।

नेतृत्व भूमिका में पीआरआई

1. पंचायत के लिए दूरदृष्टि विकसित करना, पंचायत क्या कर सकता है इसकी रूपरेखा तैयार करना
2. पंचायत संसाधन आवरण के लिए दूरदृष्टि नियोजित करना
3. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और इन लक्ष्यों को प्राथमिकता देना
4. विभिन्न सेवाओं और अधिकारों तक पहुंच को सक्षम करना
5. स्थल पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का होना
6. निगरानी निर्गम और परिणाम
7. विकास के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ सहयोग करना

5.2 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में एसएचजी की भूमिका-

1. समुदाय से बाहर हुए लोगों और कमजोर वर्गों के सामाजिक संगठन तथा पहचान के लिए उन्हें एसएचजी में लाने के लिए ग्राम पंचायत से समर्थन प्राप्त करना ।
2. गरीबों के सहभागी अभिनिर्धारण के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों के साथ काम करना और ग्राम सभा में प्रक्रिया का अनुमोदन करना ।
3. विशेषतया एमजीनरेगा के तहत कार्य और परिसंपत्तियों और जीपीडीपी से लाभ पाने में एसएचजी और एसएचजी संघ में पहले से ही सहमत रूप में समेकित मांगों के साथ ग्राम सभा में सक्रियता से सहभाग लेना ।
4. ग्राम पंचायतों को प्रचार में उनकी मदद करके, ग्राम सभा आयोजित करने, चर्चाओं और दस्तावेज़ीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करना ।
5. उचित फीस का दावा करते हुए मध्याह्न भोजन, प्रत्येक घर से करों का संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन और पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति, ई-सेवाओं आदि ग्राम पंचायतों द्वारा सौंपे गये सेवा वितरण जिम्मेदारियां उठाना ।
6. प्रत्येक एसएचजी में हक के सहभागिता आकलन (पीएई) का संचालन करना और वीओ और जीपी स्तर पर समेकित करना और हक अभिगम योजना (ईएपी) तैयार करना ।

7. एसएचजी के लिए आजीविका आधार के रूप में ग्राम पंचायत के सामान्य संसाधनों जैसे कि मछली तालाबों, आम संपत्तियों और बाजार अहाता आदि जैसे सामान्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत के साथ काम करना ।
8. ग्राम पंचायत से जानकारी प्राप्त करना और एसएचजी सदस्यों के बीच उपलब्ध सरकारी सेवाओं और योजनाओं से संबंधित मुद्दों को प्रसारित करना
9. ग्राम पंचायत और अन्य हितधारकों के सहयोग से ग्राम पंचायत गरीबी न्यूनीकरण योजना तैयार करें और इसके कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत और अन्य लाइन विभागों से पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करें ।
10. योजना और कार्यान्वयन में भागीदारी, चर्चा और निगरानी के लिए एसएचजी की सभी नियमित बैठकों में एक एजेंडा के रूप में पीआरआई-सीबीओ अभिसरण को शामिल करें ।
11. पंचायतों की योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की कार्यात्मक समितियों में सक्रिय रूप से भाग लें
12. सभी सदस्य परिवारों को कवर करने वाली सूक्ष्म ऋण योजनाएं तैयार करें, गरीबों की भागीदारी पहचान लें, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए पात्रता का सहभागी मूल्यांकन
13. उचित शुल्क का दावा करके जीपी की सेवा वितरण जिम्मेदारियां लें
14. जीपी परियोजना कार्यान्वयन के सामुदायिक निगरानी तंत्र में भाग लें
15. मछली तालाब, सार्वजनिक सम्पत्ति, बाजार यार्ड इत्यादि जैसे जीपी के सामान्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए जीपी के साथ काम करना क्योंकि यह एसएचजी का आजीविका आधार है ।
16. योजनाओं और अधिकारों के बारे में संवेदनशीलता और सूचना प्रसार की सुविधा और आईईसी सामग्री - पोस्टर, दीवार पर लेखन, फार्म / पुस्तिकाएं इत्यादि का उपयोग करके ग्राम सभा के लिए संग्रहण ।

साझेदारी भूमिका में सीबीओ
1. पंचायत विजन और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन प्रदान करते हुए ग्रामसभा और पंचायत कार्य के लिए समुदाय को संगठित करना 2. उन लाभार्थियों की पहचान करना जिनकी कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंच नहीं है, और उन्हें पंचायतों के ध्यान में लाना

3. पंचायत और उसके लोगों के बीच संचार चैनल के रूप में कार्य करना और पीडीएस, आंगनवाड़ी इत्यादि जैसे संस्थानों के कामकाज की निगरानी
4. एमएनआरईजीएस, जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना, ग्राम जल और स्वच्छता समिति जैसे पंचायत में सार्वजनिक मंचों और समितियों में एसबीएम समुदाय की बातों को पहुँचाना ।

5.3 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में राज्य सरकार की भूमिका: राज्य सरकारों को निम्नलिखित पर अभिसरण को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाना है

1. साझेदारी को साकार करने के लिए राज्य विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं। इसे सभी गहन / संसाधन खंडों में तुरंत कार्यान्वित किया जा सकता है।
2. डे-एनआरएलएम और राष्ट्रीय संसाधन संगठन (जैसे केरल के कुडुम्बश्री) के राष्ट्रीय मिशन यूनिट से तकनीकी सहायता लेना।
3. ग्राम संगठनों (वीओ) और ग्राम पंचायतों के बीच भौगोलिक अनुरूपता लाना।
4. पंचायत में वीओ के लिए स्थान देने हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित करें।
5. ग्राम पंचायत के नियंत्रण में आने वाले तालाबों, चराई भूमि जैसे संपत्ति से लाभ उठाने के लिए एसएचजी को सक्षम करने का आदेश।
6. गरीबी न्यूनीकरण योजना तैयार करने के लिए जीपीडीपी के भाग के रूप में प्रक्रिया निर्धारित करें जिसमें एसएचजी को मुख्य भूमिका दी जाती है।
7. जीपीडीपी की योजना टीमों में एसएचजीएस सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (सीआरपी) का सह-चयन करें।
8. स्पष्ट मानदंडों के आधार पर गरीबी-विरोधी कार्यक्रम के लाभभोगियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा की सहायता हेतु एसएचजी को औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपें।
9. सुनिश्चित करें कि सभी योग्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एसएचजी का सदस्य बनाया गया है।
10. ग्राम पंचायतों के साथ कम से कम वर्ष में दो बार वीओ के नियमित बातचीत के लिए मंच तैयार करें जिसमें वीओ जरूरतों को समझाएगा और ग्राम पंचायत अपने विकासात्मक समर्थन को औपचारिक रूप से लागू करेगी ...
11. साझेदारी की निगरानी के लिए वीओ और ग्राम पंचायत के नेताओं को मिलाकर संयुक्त समितियां गठित करें, इसी प्रकार यदि आवश्यक हो तो समस्या निवारण के लिए ब्लॉक स्तर पर एक समिति की स्थापना की जा सकती है।

12. 5 वें अनुसूची क्षेत्रों में, एसएचजी विशेष रूप से ग्राम सभा को मजबूत करने और उनकी क्षमता को उपयुक्त रूप से निर्माण करने में शामिल हो सकते हैं।

5.4 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण में एसआरएलएम की भूमिका: एसआरएलएम निम्नलिखित पर अभिसरण की सुविधा दे सकता है

1. एसआरएलएम को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करके फेडरेशन में सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों / स्थानीय स्त्रोत समूहों की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है।
2. डे-एनआरएलएम इसके कामकाज और एसएचजी के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (विशेष रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों) को प्रशिक्षित करें।
3. जीपीडीपी और एमजीएनआईजीएस के लिए एक सार्वजनिक राज्य स्त्रोत टीम को स्थान देना।
4. समेकित पात्रता योजना के आवधिक सत्यापन और निगरानी के लिए एम आई एस में ब्लॉक स्तर पर रखें।
5. एसएचजी नेताओं और जीपी नेताओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का आयोजन करें।

समूह कार्य / अनुभव साझा करने के लिए मॉडल प्रश्न
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ एसएचजी को कुछ सार्वजनिक सेवाओं के संचालन और रखरखाव के आउटसोर्सिंग के दायरे और इस तरह के मामलों में ग्राम पंचायतों द्वारा क्या नियामक तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए इस पर चर्चा करें➤ ग्राम पंचायतों के साथ वी ओ के नियमित बातचीत के लिए किस प्रकार का मंच तैयार किया गया, इस पर चर्चा करें➤ शासन प्रक्रिया में सुधार के लिए गरीबों के सामूहिक क्षेत्रों को विभिन्न आरडी कार्यक्रमों में कैसे शामिल और सम्मिलित किया जा सकता है |
|--|

सत्र 6:

गरीबी उन्मूलन के लिए अभिसरण सक्षम करना

सत्र उद्देश्य

- सहभागी आकलन और योजना का अर्थ और अवधारणा समझाना
- ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना का उद्देश्य
- जीपीपीपी के साथ ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना का एकीकरण

सत्र संक्षिप्त:

- विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सतत विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गरीबों के समूहों के रूप में एसएचजी किसी भी स्थानीय विकास पहल में प्रमुख चालक हो सकते हैं। जब ऐसे नागरिक संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्थानीय शासन प्रणाली के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ते हैं, तो सेवा वितरण में सुधार होता है।
- अभिसरण परियोजना में सहभागी नियोजन विधियों और उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक प्रणाली के साथ सीबीओ की निरंतर बातचीत की परिकल्पना की गई है।
- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना के दौरान विकसित तीन सहभागी योजना उपकरण में हक का सहभागी आकलन (पीआई), हकदारिता पहुँच योजना (ईएपी), और ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना शामिल (जीपी 2 आरपी) हैं।

समूह कार्य:

- प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित किया जाएगा और वे एक विषय पर समूह रिपोर्ट तैयार करेंगे और यह प्रशिक्षण सुविधाकर्ताओं के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जो रिपोर्ट पर टिप्पणी करेंगे। यह सुविधाकर्ताओं और प्रतिभागियों को शिक्षण के हस्तांतरण की सीमा का मूल्यांकन करने में सक्षम करेगा।

सत्र सामग्री-

6.1 सहभागी आकलन और योजना: विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सतत विकास एजेंडा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गरीबों के समूहों के रूप में स्व-सहायता समूह किसी भी स्थानीय विकास पहल में प्रमुख चालक हो सकते हैं। पंचायतों के साथ सीबीओ के प्रभावी जुड़ाव द्वारा गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त किए

जा सकते हैं। पीआरआई-सीबीओ अभिसरण की अवधारणा ने कल्पना की है कि उचित क्षमता तंत्र द्वारा समुदाय से बढ़ती मांग से सेवा वितरण प्रणाली में सुधार होगा। सीबीओ और पीआरआई के एक साथ मिलकर काम करने से जमीनी स्तर पर एक मजबूत लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करने में मदद मिलती है। पीआरआई-सीबीओ अभिसरण भी सार्वजनिक सेवा वितरण की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत समुदाय केंद्र और स्थानीय संस्थानों के विकास की परिकल्पना करता है।

आकलन और योजना में सामुदायिक भागीदारी की सुविधा के लिए, निम्नलिखित टूल्स विकसित किए गए हैं।

क) हक का सहभागी आकलन (पीआई): इस उपकरण का उपयोग कमजोर एसएचजी परिवारों द्वारा हकदारिता पहुंच में अंतराल को समझने के लिए किया जाता है। पीआई एसएचजी सदस्यों के संगठन को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न अधिकारों और स्थानीय प्रशासन प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है

ख) हकदारिता पहुंच योजना (ईएपी): इस उपकरण का उपयोग हक तक पहुंचने के लिए कार्रवाई की योजना बनाने के लिए किया जाता है। ईएपी उनकी हकदारिता के आकलन में मदद करता है

ग) ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना (जीपी 2 आरपी): ग्राम स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए ग्राम पंचायत (जीपी) के साथ संयुक्त रूप से योजना बनाने के लिए इस टूल का उपयोग कमजोर एसएचजी परिवारों द्वारा किया जाता है। यह समुदाय द्वारा उठाई गई मांग को पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने में मदद करता है।

6.2 हक का सहभागी आकलन (पीआई): पीआई, एसएचजी स्तरीय परस्पर संपर्क आधारित उपकरण है जो विभिन्न अधिकारों और स्थानीय-स्व-शासन प्रणाली पर जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। पीआई का उपयोग करके, समुदाय योजनाओं तक पहुंच और प्रशासन प्रक्रिया में भागीदारी पर डेटाबेस तैयार करता है। इस डेटाबेस का उपयोग सीबीओ द्वारा मांग योजना तैयार करने में किया जाता है और समुदाय द्वारा अधिकार प्राप्त करने में सफलता को मापने के लिए आधार रेखा के रूप में भी माना जाता है। ग्राम पंचायतों के स्थानीय संसाधन समूह नामक समुदाय केंद्र द्वारा पीआई कार्यों को सुविधा प्रदान की जाती है।

6.2.1 पीआई के उद्देश्य

क) ग्राम सभा और योजनाओं के लिए संवेदनशीलता और संगठन

ख) परियोजना प्रगति के आकलन के लिए डेटा संग्रहण

ग) भविष्य की गतिविधियों के लिए योजना बनाने के लिए सामग्री विकसित करना

घ) एलआरजी और ग्राम संगठन (वीओ) को सुदृढ़ करना

ड.) एसएचजी नेटवर्क से सक्रिय महिलाओं की पहचान

पीएई डेटा को वीओ प्रतिनिधियों और एलआरजी सदस्यों द्वारा जीपी स्तर पर समेकित किया जाता है। इस आंकड़ों को जीपी के सभी एसएचजी सदस्यों की उपस्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत के अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। पीएई डेटा का प्रस्तुतीकरण पंचायत और सीबीओ को शिनाख्त अधिकारों के अंतराल को कम करने के लिए एक आम मंच पर एक साथ आने का मौका देता है। संकलित डेटा को सीबीओ द्वारा बेसलाइन के रूप में माना जाता है ताकि लक्ष्य योजना को 'हकदारिता पहुँच योजना' कहा जा सके।

6.2.2 पीएई का प्रभाव

क) हक के बारे में जागरूकता

ख) एसएचजी में हक पर व्यापक चर्चा

ग) अनुवर्ती कार्रवाई के लिए हकदारिता स्थिति पर डेटा

घ) विभिन्न योजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन

ड.) हकदारिता मांगों को आगे बढ़ाने के लिए सीबीओ को सुदृढ़ करना

च) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीआरआई को समर्थन

छ) भागीदारी योजना प्रक्रिया के लिए वातावरण तैयार करना

ज) स्थिति विश्लेषण और भागीदारी योजना के लिए उपकरण

झ) समुदाय कैडर को सुदृढ़ बनाना

6.3 हकदारिता पहुँच योजना (ईएपी): ईएपी, पीएई के दौरान शिनाख्त अधिकारों तक पहुँच में अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक ग्राम संगठन (वीओ) द्वारा तैयार की गई एक लक्षित योजना है। बेसलाइन के रूप में पीएई डेटा का उपयोग करके, प्रत्येक वीओ विभिन्न योजनाओं के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करता है। वीओ द्वारा नियमित रूप से इन लक्ष्यों की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

6.3.1 पीएई के उद्देश्य

- क) ग्राम सभा और योजनाओं के लिए संवेदनशीलता और संगठन
- ख) परियोजना प्रगति के आकलन के लिए डेटा संग्रहण
- ग) भविष्य की गतिविधियों के लिए योजना तैयार करने के लिए सामग्री विकसित करना
- घ) एलआरजी और ग्राम संगठन को सुदृढ़ बनाना
- ड.) एसएचजी नेटवर्क से सक्रिय महिलाओं की पहचान

पोस्ट-ईएपी अनुवर्ती के भाग के रूप में जीपी को एसएचजी परिवारों की पात्रता पहुंच स्थिति प्रस्तुत करने और अधिक लोगों के सामने पात्रता मांग प्रस्तुत करने और पीआरआई एवं लाईन विभागों से प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत और लाइन विभागों के साथ परामर्श आयोजित किया जाना है। प्रमुख हितधारकों में हकदारिता अंतरालों को साझा किया जाते हैं और मसौदा योजना तैयार की जाती है

6.3.2 ईएपी का प्रभाव

- विभिन्न योजनाओं के लिए समेकित लक्ष्य मांग
- योजनाओं के लाभों के बारे में लक्षित समुदाय की संवेदनशीलता
- योजना तैयारी और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर पीआरआई और सीबीओ की क्षमता
- सामाजिक कल्याण योजनाओं की पहुंच को बढ़ाने में सीबीओ से पीआरआई को समर्थन
- पात्रता तक पहुंच सुनिश्चित करने में सीबीओ का स्वामित्व

6.4 जीपी स्तरीय गरीबी उन्मूलन योजना

ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना, स्थानीय विकास के लिए ग्राम पंचायतों के साथ साझेदारी में स्व-सहायता समूहों और उनके संघों द्वारा तैयार की गई एक व्यापक मांग योजना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण प्रयासों का एक अभिन्न अंग है। यह दस्तावेज मिशन और योजना दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा जिसके आसपास ग्राम पंचायत और सीबीओ, नेटवर्क, गांव में गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करता है। भागीदारी मूल्यांकन और योजना की पीएई और ईएपी विधि डे-एनआरएलएम के तहत एक व्यापक जीपी स्तरीय गरीबी उन्मूलन योजना विकसित करने की नींव हो सकती है। डे-एनआरएलएम एसएचजी में सदस्यता के साथ प्रत्येक परिवार से सामाजिक-आर्थिक जाति

जनगणना मांग का उपयोग जीपी को मांग योजना प्रस्तुत करने के लिए ग्राम और जीपी स्तरों पर एसएचजी को संग्रहित, प्राथमिकता और एकत्रित किया जा सकता है।

6.4.1 जीपी स्तर की गरीबी उन्मूलन योजना का उद्देश्य: निम्नलिखित ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना के उद्देश्य हैं

क) स्थानीय सरकारों के साथ परामर्श में सामुदायिक नेटवर्क के नेतृत्व में स्थानीय विकास के लिए व्यापक और समावेशी योजनाएं तैयार करना

ख) गरीबी उन्मूलन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय आधारित संगठनों और उनके नेतृत्व को सुदृढ़ करना

ग) उचित तंत्र के माध्यम से गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्व-सहायता समूहों और पंचायत राज संस्थानों के संघों के मध्य उचित परिचर्चा के विकास की सुविधा प्रदान करना

6.4.2 जीपी स्तरीय गरीबी उन्मूलन योजना की प्रक्रिया: जीपी स्तरीय गरीबी उन्मूलन योजना पंचायत में वीओ या वीओ के समूह द्वारा तैयार की गई योजनाओं का एकीकरण है। वीओ योजना अपने गठित एसएचजी से योजनाओं के एकीकरण द्वारा तैयार की जाती है। पूरी प्रक्रिया एलआरजी सदस्यों, सीबीओ नेताओं और एसएचजी पदाधिकारियों की आवश्यक क्षमता के माध्यम से पूरी की जाती है। प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

क) पीएई के दौरान एसएचजी स्तर पर पात्रता के पहुँच का मानचित्रण और समेकित किया जाता है। इसे 'एसएचजी आजीविका और हकदारिता योजना' बनाने के लिए सामाजिक समावेश योजना, आजीविका योजना, और एसएचजी की क्रेडिट योजना के साथ विलय किया गया है।

ख) वीओ स्तर पर समेकित एसएचजी स्तर की योजनाओं को ग्राम स्तरीय संसाधन और आधारभूत संरचना विकास योजनाओं के साथ 'ग्राम आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजना' बनाने के लिए विलय किया गया।

ग) 'ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना' तैयार करने के लिए वीओ या वीओ समूह द्वारा तैयार योजनाएं। योजना आधारित मांगों को जीपी, लाईन विभागों और डे-एनआरएलएम के आबंटन से एकीकृत किया गया है।

6.4.3 ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना (जीपी 2 आरपी) के घटक: ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना को आजीविका, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीब परिवारों

द्वारा मांग किए गए मूल आधारभूत संरचना एकत्रित करते हुए एसएचजी द्वारा तैयार किया जाता है। गरीबी उन्मूलन योजना के घटक निम्नलिखित हैं

सभा	घटक	विवरण
1	सामाजिक समावेशन योजना	डे तहत के एनआरएलएम-एसएचजी में कमजोर लोगों / योजना की करने शामिल को परिवारों
2	हकदारिता योजना	हक के सहभागी आकलन के आधार पर हक के लिए समेकित मांग
3	आजीविका योजना	कृषि, पशु पालन, कौशल प्रशिक्षण आदि के माध्यम से आजीविका में वृद्धि के लिए विशिष्ट मांग
4	ऋण योजना	डे सेवाओं वित्तीय तहत के संयोजन बैंक और एनआरएलएम-मांग की
5	आधारभूत संरचना विकास योजना	नए बुनियादी ढांचे और मौजूदा बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण की मांग
6	संसाधन विकास योजना	प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और विकास की मांग

6.4.4 जीपीडीपी के साथ एकीकरण: यह भी अनिवार्य किया गया है कि जीपी इस अनुदान के निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग और अन्य संसाधन जिन पर उनका नियंत्रण है को सुनिश्चित करने के लिए एक सहभागी योजना प्रक्रिया अपनाये। जीपीडीपी में जीपी में गरीबी के पैटर्न की पहचान करके और गरीब समूहों और इलाकों के लिए बुनियादी सेवाओं को प्राथमिकता देने जैसे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को परिवर्तित करने, गरीबी घटाव पर अधिक फोकस होना चाहिए। विभिन्न कानूनों और कार्यक्रमों के तहत दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए और योजनाओं का (पीईएसए अधिकार, वन अधिकारों) सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण) एमजीएनआरईजीएस और डे-एनआरएलएम के तहत बनाए गए संस्थानों के माध्यम से विशेष रूप से आजीविका में सुधार द्वारा उपयोग किया रहा है। गरीबी उन्मूलन और विकास के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोणों के माध्यम से प्रयासों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है और इसलिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं (पीएमएवाई, एमजीएनआरईजीएस, पीएमजीएसवाई, डे-एनआरएलएम, एनएसएपी, मिशन अंत्योदय और आरजीएसए आदि) का अभिसरण आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप अनुलग्नक मुख्य समस्याओं में 1 का समाधान

करने की क्षमता वाला प्रभावी जीपीडीपी होगा। इस प्रकार, एक समुदाय द्वारा संचालित प्रक्रिया के माध्यम से सीबीओ द्वारा तैयार जीपी 2 आरपी जीपीजीपी का मूल्य बढ़ाता है।

ग्राम पंचायत गरीबी न्यूनीकरण योजना का एक मॉडल प्रारूप अनुलग्नक 4 में दिया गया है

समूह कार्य / अनुभव साझा करने के लिए मॉडल प्रश्न

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं

- 1 ... नियोजन प्रक्रिया और ग्राम सभा में अपर्याप्त लोगों की भागीदारी।
2. अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा वितरण।
3. पीआरआई-एसएचजी अभिसरण के रूप में सामाजिक पूंजी को पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं करना।
4. जीपीडीपी में जेंडर, बच्चे, बुजुर्गों और दिव्यांगों से संबंधित मुद्दों को शामिल नहीं करना।

चर्चा करें कि सीबीओ को शामिल करने की स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है

सत्र 7: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना

सत्र का उद्देश्य

- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण को लागू करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण में प्रतिभागियों को परिचित करना।
- राष्ट्रीय संसाधन संगठन (केएस-एनआरओ) के रूप में कुडुम्बश्री द्वारा समर्थित परियोजना
- केएस-एनआरओ परियोजना के परिणाम फ्रेम कार्य
- केएस-एनआरओ परियोजना के तहत अपेक्षित उपलब्धियां क्या है

सत्र संक्षिप्ति

- अभिसरण एक दृष्टिकोण है जो लोगों के नेटवर्क के विकास, समुदाय के सदस्यों के सशक्तिकरण को सक्षम बनाने और उपलब्ध विभिन्न अधिकारों के बारे में उनके ज्ञान निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने नागरिकों द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने वाला एक सशक्त समुदाय अपने संवैधानिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियों की दिशा में पंचायत की चेतना निर्माण की ओर जाता है। एक सचेत पंचायत गरीबों के मजबूत सामुदायिक नेटवर्क के साथ काम करने की प्रक्रिया के दौरान सशक्त हो जाता है। इसलिए, पीआरआई-सीबीओ अभिसरण दृष्टिकोण गरीबी उन्मूलन-उपायों और गांव के स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को शुरू करने की प्रक्रिया में पंचायत और समुदाय के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध स्थापित करने की उम्मीद करता है। दोनों का ऐसा संबंध गरीबों और समुदाय में कमजोर आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा काम कर सकता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ) के रूप में कुडुम्बश्री को स्थापित करके अन्य राज्यों को समर्थन देने के लिए इसे मान्यता दी है। एनआरओ के रूप में कुडुम्बश्री राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के (एसआरएलएम) साथ साझेदारी का जनादेश रखता है और उन्हें तकनीकी और कार्यान्वयन समर्थन देता है। मई 2013 से एनआरओ कार्यात्मक हुई है।

भूमिका निर्वाह:

- समूह से 12-10 महिला प्रतिभागियों को आमंत्रित करें, चूंकि वे क्षेत्र में एसएचजी को समझ चुके हैं उन्हें एसएचजी बैठक आयोजित करने के लिए कहें। उन्हें तैयार होने के लिए 10 मिनट दें और नमूना एसएचजी बैठक पेश करने के लिए 10 मिनट दें। बैठक की शुरुआत के लिए के करने नोट और देखने को प्रक्रिया

10 प्रतिभागियों से कहे। एक बार रोल प्ले होने के बाद, पर्यवेक्षकों से पूछें कि उन्होंने रोल प्ले में क्या देखा। पर्यवेक्षकों द्वारा जो कहा जाता है, उसके आधार पर, एसएचजी पर चर्चा शुरू कर के बताये कि वे केवल मितव्ययी और क्रेडिट सोसायटी नहीं हैं बल्कि उससे अधिक हैं।

सत्र सामग्री-

7.1 राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ): कुडुम्बश्री केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है ... ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कुडुम्बश्री को 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय संसाधन संगठन (केएस- एनआरओ) के रूप में पहचाना है। केएस-एनआरओ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के लिए तकनीकी और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करता है जो इसके साथ साझेदार है। पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) और समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) के बीच अभिसरण बढ़ाने का प्रयास है। परियोजना सीबीओ-पीआरआई इंटरफ़ेस को मजबूत करने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का उपयोग करती है। परियोजना मूल रूप से समुदाय केंद्रित नेटवर्क के साथ पंचायतों द्वारा निर्धनता केंद्रित कार्यक्रमों की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और बेहतर भागीदारी योजना को बढ़ाने की मांग करती है।

7.2 परियोजना लक्ष्य

1. प्रक्रियाओं को शुरू करें जो सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न पात्रताएँ और योजनाओं के तहत लाभ एसएचजी के सदस्यों को डे-एनआरएलएम के तहत अर्जित करना
2. स्थानीय स्व-सरकारी प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करना
3. पंचायत राज प्रणाली को समाज, विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में योगदान देना
4. अभिसरण की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सामुदायिक संस्थानों और स्थानीय सरकारों के साथ काम करने के लिए सामुदायिक व्यावसायियों के एक कैडर को विकसित करने में सहायता करना
5. महिलाओं को उनके हकों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी जिनसे उनको फायदा होगा और स्थानीय स्तर की प्रक्रिया पर ज्ञान और जागरूक करना
6. पीआरआई द्वारा योजना, पीआरआई प्रणाली और विकास योजनाओं के तरीके को प्रभावित कर सकती है।
7. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय स्तर की योजना की प्रभावशीलता में सुधार किया है।

7.3 कुडुम्बश्री-एनआरओ के मार्गदर्शन सिद्धांत

1. **संदर्भित दृष्टिकोण:** केएस-एनआरओ का मानना है कि प्रत्येक स्थान को अपने विशेष संदर्भ के लिए अनुकूल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसलिए, केएस-एनआरओ कुडुम्बश्री के अनुभव से आकर्षित होता है, और अपने राज्यों में कार्यान्वयन के लिए गतिविधियों को अनुकूलित करने के लिए अपने साथी-एसआरएलएम के साथ काम करता है।

2. **समेकन और विस्तार के लिए स्थानीय क्षमताओं का निर्माण:** केएस-एनआरओ साझेदार-राज्यों में स्थानीय संसाधन पूल बनाने पर केंद्रित है। यह रणनीति इस समझ के आधार पर है कि स्थानीय लोग अपने समुदाय के लिए काम करने के लिए बेहतर स्थान पर हैं। पायलट अवधि के बाद परियोजना गतिविधियों की स्थिरता और विस्तार सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत समुदाय कैडर से उम्मीद की जाती है।

3. **अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सलाह देना:** केएस-एनआरओ केरल में कुडुम्बश्री के साथ काम करने के अनुभव के साथ स्रोत व्यक्तियों को चुनता है और साझेदार-राज्यों में सलाहकार के रूप में कार्य सौंपता है। सलाहकार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय समुदायों और साझेदार-एसआरएलएम को दिन-प्रति-दिन अनुभव समर्थन प्रदान करते हैं।

4. **निगरानी, प्रशिक्षण और अनुभव के लिए व्यावसायिक समर्थन:** केएस-एनआरओ के पास व्यावसायिकों की एक टीम है जो पार्टनर-राज्यों में सलाहकारों और स्थानीय स्रोत व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए बैक-एंड समर्थन प्रदान करती है। भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से तैयार ये व्यवसायी, परियोजनाओं के लिए निगरानी, प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सिस्टम विकसित करते हैं, केएस-एनआरओ साझेदार-राज्यों में समर्थन करता है।

7.4 सीबीओ-पीआरआई अभिसरण परियोजना राज्य: 22 जिलों और 386 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 8 राज्यों में परियोजना लागू की जा रही है

राज्य	जिले	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
असम	2	2	36
झारखंड	4	6	29
कर्नाटक	2	4	40
महाराष्ट्र	3	3	58
ओडिशा	4	4	12
राजस्थान	3	3	67

सिक्किम	2	7	53
गोवा	2	5	91
	22	34	386
स्रोत केएस-एनआरओ परियोजना			

7.5 प्रोजेक्ट का परिणाम ढांचा कार्य: डे-एनआरएलएम ने कुडुम्बश्री समर्थन के साथ एसआरएलएम द्वारा प्रारंभ पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजनाओं की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए एक परिणाम ढांचा विकसित किया है ... अभिसरण के लिए परिणाम फ्रेमवर्क निम्नानुसार है।

7.5.1 शासन प्रक्रिया सुधार- राज्य सरकार पंचायतों की उप समितियों में सीबीओ सदस्यों को शामिल करने सहित अभिसरण के लिए नीति दिशानिर्देशों और परिचालन ढांचे के साथ उभरेगी ... पीआरआई और सीबीओ के कार्यकलाप से संबंधित शासन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में किए गए सुधार को मापा जाएगा

7.5.2 घरेलू लाभ परिणाम- गरीब परिवारों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के कारण अर्जित परिणामों को मापना। परियोजना गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं

1. प्रशिक्षित महिला ईआर सहित निर्वाचित प्रतिनिधि (ईआर) की संख्या और अनुपात
2. प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों और वीओ नेताओं की संख्या और अनुपात
3. पायलट परियोजना के अंत में प्रशिक्षित एलआरजी सदस्य और सक्रिय सदस्यों की संख्या
4. नए एसएचजी और बनाई गई वीओ की संख्या और पुनर्जीवित निष्क्रिय एसएचजी
5. पायलटों की प्रतिकृति के लिए एसआरएलएम द्वारा उठाए गए जीपी और ब्लॉक की संख्या

7.4.3 कुडुम्बश्री एनआरओ का अनुभव: साझेदार राज्यों में पीआरआई के साथ काम करते समय केएस-एनआरओ ने निम्नलिखित मील का पत्थर हासिल किया है।

1. अग्रगामी राज्यों में एसएचजी ने योजनाओं के बारे में ज्ञान बढ़ाया है, अनौपचारिक रूप से लाभार्थियों की पहचान की है और पात्रता पहुँच में अंतर को दस्तावेज किया है।
2. एसएचजी ने अपने अधिकारों और हकों तक पहुंचने और ग्राम पंचायतों के साथ संयुक्त कार्रवाई करने की योजना बनाई है।
3. साझेदार राज्यों में, एसएचजी नेटवर्क प्रासंगिक योजना तैयार करने में सक्षम रहा है, जो अगली योजना प्रक्रिया में सफलतापूर्वक शामिल हो गया है।
4. एसएचजी से महिलाओं के नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास में सुधार हुआ है, जैसा कि ग्राम सभा में महिला प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि और विचार-विमर्श की गुणवत्ता और मांगों की गुणवत्ता में स्पष्ट है।

5. सीबीओ, ग्राम पंचायत और लाइन विभागों के प्रतिनिधियों सहित गठित समिति पीआरआई और सीबीओ की प्रभावी साझेदारी के लिए मंच के रूप में कार्य करता है।
6. साझेदार राज्यों में, विभिन्न गतिविधियों के लिए पहल की गई हैं जैसे कि बैंक खाते खोलने के लिए अभियान, साक्षरता जागरूकता, बाल सभाओं का गठन, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, जॉब कार्ड भोजन और पेंशन आदि।

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना:

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना महिलाओं के एसएचजी नेटवर्क के डे-एनआरएलएम ढांचे के भीतर काम करती है। परियोजना का जोर हमेशा महिलाओं पर रहा है और इस तरह, संसाधनों की पहचान और विकास समुदाय के भीतर की जाती है। इस दृष्टिकोण का एक लाभ यह है कि महिलाएँ जमीन की वास्तविकताओं के बारे में समझ सकती हैं। कठोर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण सत्र महिलाओं को पर्याप्त कौशल और ज्ञान के साथ लैस करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी बातचीत क्षमताएं बेहतर होती हैं। परियोजना न केवल एसएचजी नेटवर्क को बल्कि पीआरआई की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी करता है। यह स्थानीय भागीदारी राज्य में सामूहिक शक्तियों के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। परियोजना का आसन्न उत्पादन विकास की जरूरतों और सामाजिक रूप से पिछड़े एवं कमजोर महिलाओं के अधिकारों के अंतराल को पूरा करना है

समूह कार्य / अनुभव साझा करने के लिए मॉडल प्रश्न

1. ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में एसएचजी क्या भूमिका निभा सकते हैं?
2. केस स्टडीज पीआरआई-सीबीओ परियोजना मामला अध्ययन पर चर्चा करें और गरीबों, ग्राम पंचायत, लाइन विभागों और एसआरएलएम संस्थानों के बीच प्रभावशीलता अभिसरण का विश्लेषण करें।

सत्र 8:

पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के अपेक्षित निष्कर्ष और परिणाम

सत्र उद्देश्य

- पीआरआईसीबीओ रूपांतरण के अपेक्षित निष्कर्ष और परिणाम क्या हैं, समझाएं

सत्र संक्षिप्ति:

पीआरआई और सीबीओ को एक साथ लाते हुए प्रभावी सामुदायिक भागीदारी और भागीदारी योजना हासिल की जा सकती है। पंचायतों द्वारा संचालित गरीब केंद्रित कार्यक्रमों की दक्षता और पहुंच सीबीओ को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदार बनाने द्वारा सुधारा जा सकता है ... एक सचेत पंचायत, मजबूत समुदाय नेटवर्क के साथ काम करने की प्रक्रिया में अधिकार सशक्त होती है इसलिए, पीआरआई-सीबीओ अभिसरण दृष्टिकोण गरीबी उन्मूलन उपायों, गांव के स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को शुरू करने की प्रक्रिया में पंचायत और समुदाय के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध स्थापित करने की उम्मीद करता है।

गतिविधि: भूमिका निर्वाह

इस बिंदु पर दूसरी रोल प्ले गतिविधि का आयोजन करें क्योंकि प्रतिभागियों ने विकास एजेंसियों के रूप में एसएचजी की समग्र अवधारणा को समझ लिया है। 10-12 महिला प्रतिभागियों से यह पूछें कि उनके अनुभव और समझ के अनुसार एसएचजी मीटिंग क्या है। उन्हें यह सोचने के लिए कहें कि सामान्य बचत और क्रेडिट गतिविधियों के अलावा एसएचजी मीटिंग्स का क्या हिस्सा हो सकता है। माँक एसएचजी बैठक 10-15 मिनट के लिए चलने दें ... उन्हें बताएं कि यह रोल प्ले पहले की रोल प्ले से काफी अलग होना चाहिए। उन्हें अपनी एसएचजी मीटिंग की चर्चाओं में निम्नलिखित अंक शामिल करने के लिए भी कहें

- क) ग्राम पंचायत से उनकी आवश्यकता के लिए मांग योजना बनाना
- ख) एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड पंजीकरण और कार्य पहचान पर चर्चा
- ग) गांव में अगली ग्राम सभा में भाग लेने पर चर्चा
- घ) पंचायत में आंगनवाड़ी के कामकाज की निगरानी, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन प्राप्त करना, जैसी कुछ अन्य विकास मुद्दों पर चर्चा

इसे तैयार करने के लिए उन्हें 10-15 मिनट दें, और फिर उन्हें प्रदर्शन करने के लिए कहें। पर्यवेक्षकों से नोट करने के लिए कहें कि वे जो भी सोचते हैं वह पिछली रोल प्ले से अलग है।

सत्र सामग्री-

8.1 अपेक्षित निष्कर्ष: निम्नलिखित पीआरआई-सीबीओ के अपेक्षित निष्कर्ष इस प्रकार है

1. व्यक्तिगत अधिकारों, सामुदायिक सेवाओं, सार्वजनिक सामान और सामाजिक सुरक्षा के लिए एसएचजी परिवारों और समुदायों की बढ़ी हुई पहुंच । उदाहरण के लिए: एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड, एमजीएनआरईजीएस काम और संपत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक पहुंच, स्कूलों और आंगनवाड़ी के उचित कामकाज, मध्याह्न भोजन, शिक्षा अधिकार अधिनियम और खाद्य अधिनियम अधिकार के तहत पात्रता सुनिश्चित करना, टीकाकरण में वृद्धि, संक्रमणीय रोगों की घटनाओं में कमी आदि
2. साझेदारी प्लेटफॉर्म और सक्रिय सामुदायिक कैडर का नियमित कार्य । उदाहरण के लिए: कार्यकारी समितियों की नियमित बैठक और समितियों में एसएचजी सदस्यों की भागीदारी के स्तर, ग्राम पंचायत आदि के लिए सामुदायिक कैडर के रूप में काम कर रहे एसएचजी सदस्यों की संख्या ।
3. ग्रामसभा में महिलाओं की वृद्धित भागीदारी और विभिन्न संस्थागत और विकास समितियाँ जैसे आंगनवाड़ी माताओं की समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, जल और स्वच्छता समितियां आदि।
4. ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना, प्रत्येक पंचायत में वीओ के साथ ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है ।
5. वितरण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एसएचजी को सौंपी गई सेवाएं।
6. सीआरपी के रूप में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या ।
7. ग्राम पंचायत द्वारा एसएचजी और उनके संघों को प्रदान की गई निधियां

8.2 अपेक्षित परिणाम: निम्नलिखित पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के अपेक्षित परिणाम है ।

1. ग्राम पंचायत से स्थानीय आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और अंत्योदय के लिए वृद्धित योगदान ।
2. गरीबी के मुद्दों पर और समुदाय संस्थानों के साथ काम करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की बढ़ी हुई क्षमता और संवेदनशीलता ।
3. साझेदारी गतिविधियों की योजना और निगरानी के लिए संयुक्त संस्थागत प्लेटफार्मों का सतत कार्यप्रणाली ।
4. स्थानीय सरकारों में निर्वाचित पदों सहित सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों तक पहुंचने के लिए महिलाओं की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाना ।

8.3 पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के लाभ: निम्नलिखित पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के कुछ फायदे हैं

8.3.1 योजना अभ्यास: गरीबों के संस्थानों का निर्माण करते हुए, गरीब स्वयं को व्यवस्थित करने और स्वयं योजना बनाने में सक्षम होंगे। गरीबों के संस्थानों के साथ काम करके पंचायत निचले स्तर तक पहुंचने के लिए सूचना प्रसार के वाहन के रूप में उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। अतः रणनीति समुदाय आधारित संगठनों के साथ काम करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य पंचायतों का उपयोग करने की मौजूदा क्षमता का उपयोग करना है। एक सशक्त और लोकतांत्रिक रूप से जागरूक समुदाय, स्थानीय सरकारी संस्थानों की प्रभावशीलता और वितरण तंत्र को मजबूत करेगा।

8.3.2 संसाधनों का पर्याप्त उपयोग: पीआरआई-सीबीओ अभिसरण सार्वजनिक सेवा वितरण की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मजबूत समुदाय केंद्र और स्थानीय संस्थानों के विकास की परिकल्पना करता है। लिकेज गरीबी उन्मूलन उपायों, स्थानीय अर्थशास्त्र और गांव के सामाजिक विकास को शुरू करने की प्रक्रिया में पंचायत और समुदाय के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। अपने अधिकारिक नागरिकों द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने वाला कोई सशक्त समुदाय पंचायत को ग्राम विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के पर्याप्त उपयोग की दिशा में संवेदनशील बनाता है।

8.3.3 कार्यक्रमों का कार्यान्वयन: पंचायतों द्वारा संचालित गरीब केंद्रित कार्यक्रमों की दक्षता और पहुंच को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सीबीओ की सक्रिय भागीदारी द्वारा सुधार किया जा सकता है। पंचायतों द्वारा उनकी कई संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए एक सक्रिय उपकरण के रूप में सीबीओ का उपयोग किया जा सकता है। यह अवसर सीबीओ को हकदारिता के लिए उनके अधिकारों और क्षमताओं की मांग करने के प्रति संवेदनशील बनने में सक्षम बनाता है। एक सशक्त और लोकतांत्रिक रूप से जागरूक समुदाय बदले में स्थानीय सरकारी संस्थानों की प्रभावशीलता और वितरण तंत्र को मजबूत करेगा। पीआरआई-सीबीओ अभिसरण समुदाय उन्मुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने और कल्याण कार्यक्रमों के वितरण के साथ-साथ अधिकारों तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी पद्धति है।

अनुलग्नक -1		
प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पीआर		
योजना का नाम	पीआरआई की भूमिका	सीबीओ की भूमिका
आईसीडीएस	वार्षिक पंचायत विकास योजना के तहत ग्राम महिला और बाल विकास योजना तैयार करना • बच्चों और महिलाओं की महसूस की गई जरूरतों को ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में शामिल करना • ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति का गठन • आंगनवाड़ी के कामकाज की निगरानी करना	गांव में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए परियोजना योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत का समर्थन करना । • आईसीडीएस के प्रत्येक घटक के लिए लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें आंगनवाड़ी में नामांकित करना • स्थानीय समर्थन प्रदान करते हुए सीबीओ नेटवर्क के माध्यम से आईसीडीएस के लिए सकारात्मक वातावरण का सृजन • अपने इलाके में प्रत्येक आंगनवाड़ी की माँ की समिति के बेहतर कामकाज में योगदान • सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए एनएचएम के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ संलग्न होना • स्थानीय त्यौहार आयोजित करना और आंगनवाड़ी के साथ सहयोग में विशेष दिन मनाना
	जॉब कार्ड आवेदन पत्र का वितरण और सत्यापन • जॉब कार्ड के लिए परिवारों को पंजीकृत करना • जॉब कार्ड जारी करना • काम के लिए आवेदन प्राप्त करना और आवेदनों	जागरूकता और प्रचार अभियान का आयोजन • श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा और नौकरी कार्ड का वितरण

एमजीएनआरईजीए	के लिए दिनांकित रसीद जारी करना • कार्यों की पहचान और योजना, परियोजनाओं की शेल्फ विकसित करना • जागरूकता उत्पादन और सामाजिक जुटाव • योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए ग्राम सभा का आयोजन • ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी • मांग के अनुसार रोजगार प्रदान करना • कार्य स्थल पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना • अन्य विभागों और परियोजनाओं के साथ संभावित अभिसरण का पता करना • हर वार्ड और जीपी स्तर पर महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस आयोजित करना	• सबसे पहले काम की मांग एसएचजी स्तर पर उत्पन्न होती है और फिर ग्राम सभा पहुँचती है • सीबीओ के सहायक प्रत्येक वार्ड से रोजगार की मांग को रेखांकित करता है और कार्यान्वयन का प्रबंधन करता है • इंजीनियरों की देखरेख में एमजीएनआरईजीएस के लिए कार्यों और स्थलों की पहचान • सीबीओ कार्य योजना के साथ पहचाने गए मनरेगा कार्यों के संभावित एकीकरण का मानचित्रण • श्रम बजट की तैयारी में भागीदारी • मनरेगा के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा में सीबीओ सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य है • सीबीओ सदस्यों द्वारा क्षेत्र निगरानी की सुविधा
एसबीए	बेसलाईन सर्वेक्षण का आयोजन करना और नियमित अंतराल पर इसे अपडेट करना • शौचालयों के निर्माण के लिए संग्रहण • शौचालय के नियमित उपयोग को बढ़ावा देना • शौचालयों का रखरखाव और मरम्मत • स्वच्छता शिक्षा के लिए पारस्परिक संचार को बढ़ावा देना • यदि आवश्यक हो तो सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए पहल करना • कार्यक्रम के प्रेरणा, संचालन, कार्यान्वयन और	खुले में शौच और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के खिलाफ संवेदनशीलता • योग्य परिवारों के सर्वेक्षण और पहचान में पीआरआई का समर्थन करना • सुनिश्चित करें कि प्रत्येक एसएचजी परिवार में आईएचएचएल है • शौचालय बनाने के लिए एसएचजी सदस्यों के लिए ऋण प्रदान करना • स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने के लिए सीबीओ को प्रशिक्षण दिया जा

	पर्यवेक्षण के संबंध में समर्थन प्रदान करने के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन।	सकता है • स्वच्छता दूत के रूप में नामांकन करके पीआरआई का समर्थन करना • एसएचजी ग्रामीण स्वच्छता सहायक के रूप में काम कर सकते हैं • सामुदायिक शौचालय प्रबंधित करना • सीबीओ नेटवर्क के माध्यम से स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी सार्वजनिक इमारतों में शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
एनएसएपी	एनएसएपी के बारे में जागरूकता सृजन और इसके तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया। • स्वैच्छिक संगठन की भागीदारी को सहयोग / क प्रोत्साहित करना • ग्रामसभा के माध्यम से लाभार्थियों के लिए पहचान और प्राथमिकता प्रक्रिया आयोजित करना। • मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना • मंजूरी और वितरण में देरी को संबोधित करने में निगरानी और अनुवर्ती • ग्राम सभा में आवधिक समीक्षा और चर्चा	पात्र लाभार्थियों की पहचान और एसएचजी आवेदन में बैठकों की संघ / क एकत्रित / वितरित करना • औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवेदकों का समर्थन करना। • लाभार्थी सूची की जांच और अंतिम रूप देने में पंचायत का समर्थन करना • लाभार्थियों को लाभों का वितरण सुनिश्चित करना और पंचायत के साथ शिकायतों को साझा करना
पीडीएस	विक्रेताओं की निगरानी • राशन कार्ड प्राप्त करने में नागरिकों का समर्थन करना • लाभार्थियों की उचित पहचान सुनिश्चित करना • लाभार्थियों को अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है को सुनिश्चित करना • पीडीएस के तहत वितरित राशन की गुणवत्ता	पीडीएस के तहत अपने अधिकार पर ग्रामीणों के बीच जागरूकता का सृजन • लाभार्थियों की पहचान में पीआरआई और लाइन विभाग का समर्थन करना • पीडीएस के तहत पात्रता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरतमंदों की सहायता करना

	की निगरानी करना	• पंचायत के साथ गलत काम का मुद्दा उठाएं
मध्याह्न भोजन	स्कूल प्रबंधन समिति गठन (एसएमसी) को सुनिश्चित करना • भोजन की गुणवत्ता की निगरानी करना • रसोईघर में स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करना • यह सुनिश्चित करना कि एसएमसी की नियमित बैठकें होती हैं • गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना	माता में स्कूल से रूप नियमित को पिता-प्रोत्साहित किए के भेजने को बच्चों अपने करना • एसएमसी की नियमित बैठकों में भाग लेना • नियमित रूप से एमडीएम में दी गई खाद्य गुणवत्ता की निगरानी करना • रसोई में सफाई सुनिश्चित करना • अपने विभिन्न कार्यों को करने में स्कूलों को समर्थन प्रदान करना
एनआरएचएम	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) गठन करने में लाइन विभाग के साथ समन्वय • स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित दौरा और दवाइयों, डॉक्टरों की अनुपलब्धता के मामले में संबंधित अधिकारियों को रिपोर्टिंग • आशा श्रमिकों के साथ नियमित समन्वय, जीपी की स्वास्थ्य स्थिति पर अद्यतन पाने के लिए एएनएम • सभी बच्चों के जन्म पंजीकृत हैं और संस्थागत प्रसव को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना • स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना • सबसे महत्वपूर्ण रोगी के परिवारों की पहचान करना और चिकित्सा सुविधा तक पहुंचने के लिए	स्वास्थ्य समस्याओं और मौसम आधारित बीमारियों पर जागरूकता सृजन अभियान चलाना • आशा श्रमिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थन करना कि सभी बच्चों के जन्म पंजीकृत हैं • अत्यंत महत्वपूर्ण रोगी के परिवारों की पहचान करना और चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन करना • आशा श्रमिकों, वीएचएसएनसी, स्वास्थ्य शिविर इत्यादि की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाना। • जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर इत्यादि में भाग लेने के लिए सदस्यों को मोबिलिज़ करना • एसएचजी और वीओ की नियमित

	उनका समर्थन करना • वीएचएसएनसी की नियमित बैठकों और अनुदान के उचित उपयोग सुनिश्चित करना	बैठकों में स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करना
प्राथमिक शिक्षा	स्कूलों में उचित आधारभूत संरचना सुनिश्चित करना • शिक्षकों की उपलब्धता की निगरानी करना • छोड़े गए स्कूली बच्चों की संख्या को कम करने के लिए कदम उठाना • शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की नियमित निगरानी • लड़की की शिक्षा के लिए केंद्रित अभियान चलाना • शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल करना	सभी बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए अभियान चलाना • प्लेटफार्म के रूप में एसएचजी नेटवर्क और वीओ का उपयोग करके, सुनिश्चित करें कि पंचायत में बच्चों ने स्कूल नहीं छोड़ा है • शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में नियमित दौरे करना • पंचायतों के साथ दूराचारों पर विचार करना
डीडीयू-जीकेवाई	कौशल विकास के लिए युवाओं को संगठित करने के लिए कदम उठाना • विभिन्न अभियान, उम्मीदवारों की पहचान करने में लाइन विभागों को समर्थन देना • सूचना प्रसार के लिए विशेष बैठकों, ग्राम सभा का आयोजन करना • संबंधित विभाग के साथ उम्मीदवारों को जोड़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना	बैठकों, अभियानों के माध्यम से इस योजना पर जागरूकता निर्माण करना • पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों की पहचान में पंचायत और लाइन विभाग के साथ समन्वय करना • संबंधित विभाग के साथ उम्मीदवारों को जोड़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना
पी एम ए वाई	उचित प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान करना • पीएमएवाई के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया की सुविधा करना • ग्राम सभा के साथ लाभार्थी सूची साझा करना • लाभार्थियों को उनके चयन या गैर पर चयन-	पात्र लाभार्थियों की पहचान और प्राथमिकता में समर्थन देना • आवेदन पत्र प्राप्त करने और भरने की प्रक्रिया में सीबीओ सदस्यों को समर्थन देना • ग्राम सभा में भागीदारी के लिए

	करना सूचित • किस्तों के समय पर वितरण के लिए लाइन विभाग के साथ समन्वय करना	एसएचजी नेटवर्क को संगठित करना
पीएम जन धन योजना	आवेदन पत्र प्रदान करना • खाते खोलने की प्रक्रिया की सुविधा • जागरूकता निर्माण के लिए विशेष बैठकें, ग्राम सभा बुलाना • लाइन विभाग के साथ समन्वय	जागरूकता निर्माण • सभी एसएचजी सदस्यों के पास उनके व्यक्तिगत बैंक खाते, वित्तीय संस्थानों तक पहुंच है, सुनिश्चित करना • खाता खोलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सदस्यों की सहायता करना

परिशिष्ट 2

मामला अध्ययन 1: "अमर गांव अमर अचोनी - जीपी2आरपी और असम में बनाए गए आंतरिक सड़के"

(पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना के लिए टूल किट : केएस-एनआरओ परियोजना असम)

सतरगांव पंचायत असम के नागांव जिले के बजिया ब्लॉक में स्थित है। इसकी जनसंख्या 6808 है। 2014 में परियोजना की शुरुआत से, पंचायत में आंतरिक सड़कों का निर्माण राजनीतिक नेताओं के भारी दबाव के कारण मुश्किल था। सलाहकार बैठकों और ग्राम सभा के दौरान, यह स्पष्ट था कि पंचायत के भीतर लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई भूमिका या शक्ति नहीं थी। इसके कारण हकों तक पहुंच के संबंध में प्रगति भी सीमित थी। स्थानीय राजनीतिक नेताओं की अनुमति के बिना सामुदायिक नेटवर्क अपने आप पर एक गतिविधि करने के लिए यह एक बड़ा दबाव था। इसलिए, पीआई और ईएपी जैसी सहभागिता योजना गतिविधियां केवल जीपी में ग्राम पंचायत और सामुदायिक नेटवर्क के साथ संबंध बनाने के संबंध में सीमित प्रभाव डाल सकती हैं।

जीपी2आरपी को पंचायत में 2016 के आरंभ में एलआरजी सदस्यों के प्रशिक्षण और बाद में एलआरजी द्वारा सीबीओ नेताओं के प्रशिक्षण के साथ शुरू किया गया था। प्रत्येक उद्देश्य से तीन सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया गया था। क्षमता निर्माण की प्रक्रिया ने एलआरजी सदस्यों की क्षमता को उस स्तर तक बढ़ाया जहां वे सलाहकारों और प्रशिक्षकों की भूमिका निभा सकते थे। चूंकि जीपी2आरपी पहला अनुभव था जिसमें सामुदायिक नेटवर्क को खुद के लिए योजना तैयार करने का मौका मिला, इसने समुदाय संगठन की मौजूदा संस्थागत संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक एसएचजी की व्यक्तिगत योजना तैयार की गई और ग्राम संगठन को सौंपी गई। जीपी2आरपी योजना के विभिन्न घटकों ने उन्हें विभिन्न लाइन विभागों के साथ संलग्न किया। अध्ययन जो कि सीबीओ का खुलासा किया गया था, किफायती और क्रेडिट गतिविधियों के लिए केवल डीआई-एनआरएल समूहों से महिला समूहों की प्रभावहीनता के विरुद्ध लड़ने के लिए एसएचजी नेटवर्क के भीतर मूक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। धीरे-धीरे, वीओ मजबूत हो गए और वीओसीसी के गठन ने समुदाय को राजनीतिक नेताओं के सामने महिला समूहों का एकीकृत चेहरा पेश किया।

सुव्यवस्थित एसएचजी संघों ने वीओसीसी के नेतृत्व में अपने अधिकारों और अधिकारों की मांग शुरू कर दी। ग्राम पंचायत के साथ लगातार संघ बैठक और सलाहकार बैठकों ने धीरे-धीरे सतरगांव जीपी में परिदृश्य बदल दिया। जब सीबीओ नेतृत्व पंचायत के संसाधन और बुनियादी ढांचा मानचित्र तैयार करने में सक्षम था, तो गांव के विकास में सामुदायिक नेटवर्क की भूमिका की सराहना की गई। सीबीओ की संभावना की मान्यता

इस तथ्य से स्पष्ट है कि पंचायत ने जीपी2आरपी योजना को उनके द्वारा तैयार की गई जीपीडीपी योजना के साथ एकीकृत किया है। वीओसीसी द्वारा दी गई 10 प्राथमिकताएं मांगें थीं, जिन्हें पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। मांगों में से एक पंचायत में 10 वार्डों में सड़कों की मरम्मत थी। इन चार सड़कों की मरम्मत के लिए निधि मंजूर कर दी गई है और इन क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है।

कृषि विभाग के साथ वीओसीसी के संपर्क से, एसएचजी सदस्यों को उनके द्वारा दी गई मांगों के आधार पर विभिन्न सामग्रियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि और पशु चिकित्सा विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी योजना बनाई जा रही है। सामाजिक समावेशन योजना के आधार पर, एसएचजी सदस्यों द्वारा अभिनिर्धारित 251 सदस्यों को एसएचजी संघ में शामिल किया गया है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत काम करने की मांग करने वाले 40 युवाओं में से 13 को पहले ही नियोजित किया गया है। सुतरगांव और असम के कई अन्य पंचायतों में यह परिवर्तन देखा गया है, एसएचजी महिलाओं के आत्मविश्वास के स्तर में असाधारण परिवर्तन के कारण और उनकी मांगों का पालन करने में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इसने गरीबों के संस्थानों और पंचायत, लाइन विभागों और एसआरएलएम जैसे विभिन्न संस्थानों के बीच प्रभावी अभिसरण का भी नेतृत्व किया है।

परिशिष्ट 3:

मामला अध्ययन 2- ओडिशा में पीआरआई-सीबीओ अभिसरण परियोजना

ओडिशा में अनुमानित 2,71,559 महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) हैं। ओडिशा आजीविका मिशन (ओएलएम) की स्थापना जुलाई 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीआई-एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को उनके आत्मनिर्भर और सामुदायिक प्रबंधित संस्थानों के विकास के माध्यम से बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, ओएलएम ने केएस एनआरओ के साथ पीआरआई-सीबीओ अभिसरण के लिए साझेदारी में प्रवेश किया है

अभिसरण संचालन जिलों के चार चयनित ब्लॉक - मलकांगिरी (मलकांगिरी), गजपति (गुमा), जजपुर (धर्मशाला) और सुंदरगढ़ (बलिसंकर) के बारह पंचायतों में लागू किया गया है। चयनित क्षेत्रों ने ओडिशा राज्य की विविधता को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीआई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम (एनआरएलपी) और गरीबी उन्मूलन तथा अवसंरचना (टीआरआईपीटीआई) ब्लॉक के लिए लक्षित ग्रामीण हस्तक्षेप से चयन किया गया है। चयनित क्षेत्रों में पीआरआई और सीबीओ सामर्थ्य पर्याप्त रूप में बदल जाता है। पीआरआई-सीबीओ अभिसरण संचालन का कार्यान्वयन ओएलएम की गहन ब्लॉक रणनीति के साथ निकट बने रहा है। सभी ब्लॉकों में मिशन टीम है। परियोजना में कई गतिविधियां गहन ब्लॉक रणनीति में अनुपालन की जा सकती हैं।

अपने सशक्त नागरिकों के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने वाला सशक्त समुदाय अपनी संवैधानिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति पंचायत की चेतना निर्माण के फलस्वरूप है। चूंकि लोगों के पास कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए सीमित ज्ञान है, इसलिए ओडिशा की पीआरआईआईआरबीओ परियोजना मौजूदा सीबीओ और संवैधानिक रूप से अनिवार्य पीआरआई को एक साथ लोगों की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए लायी गई है।

References:

1. Guidelines for Preparation of Grama Panchayat Level Development Plans, , Ministry of Panchayat Raj (MoPR), New Delhi. Lr.No. M- 11015/249/2015-DPE November 4,2015
2. Panchayat –SHG convergence for participatory planning at Gram Panchayat level-Advisory of MoPR-Government of India, Ministry of Panchayati Raj New Delhi, - Lr,No No. K-11022/31/2015-CB February 4, 2016.
3. Panchayat Self Help Group Convergence at Gram Panchayat level- Government of

India Ministry of Rural Development Department of Rural Development New Delhi Lr .No Misc./2018-GSA May 22, 2018

4. Gram Panchayat Development Plans and Women Collectives - Charting New Territory: Sarada Muraleedharan IAS Joint Secretary, Ministry of Panchayat Raj (MoPR), Government of India, New Delhi , KILA Journal of Local Governance 2(2), July-December, 2015 pp 1-8
5. Toolkit for PRI-CBO convergence- Enabling Convergence: Kudumbashree National Resource Organisation -
https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/PRI-CBO%20Convergence%20Toolkit_KS-NRO.pdf
6. Guidelines for Release and Utilization of Grant Recommended by the Fourteenth Finance Commission (FFC) for Rural and Urban Local Bodies Lr. No. 13 (32) FFC/FCD/2015-16 dated 08/10/2015, Ministry of Finance, New Delhi
7. Community Professionals for Convergence- Facilitators Manual: Kudumbashree Kerala State Poverty Eradication Mission Government of Kerala.
<https://aajeevika.gov.in/sites/default/files/CPC%20Facilitator%27s%20Manual.pdf>